लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २५, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXV, 1964/1885 (Saka)

[१० से २१ फरवरी, १९६४/२१ माघ से २ फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[February 10 to 21, 1964/Magha 21 to Phalguna 2, 1885 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 27-5-92
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

(Vol. XXV contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1228(Ai)LSD—I

विषय सूची

अंक ७—मंगलवार, १८ फरवरी, १९६४/२९ माघ, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५०.	जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	४७३—७४
१५१.	चीनी का उत्पादन	४७५—७८
१५२.	कृषि उत्पादन	४७८—८०
१५३.	उत्तर प्रदेश के लिये चीनी का अभ्यंश	४८०—८२
१५४.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एवरो-७४८ की खरीद	४८२—८४
१५७.	कृषि उत्पादन बोर्ड	४८४—८७
१५८.	निर्यात वस्तुओं पर भाड़ा	४८७—८८
१५९.	चीनी का वितरण	४८८—९२
१६०.	पी० एल० ४८० करार	४९२—९३
१६१.	विशेष डाक टिकट	४९४—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
१५५.	कृषि उत्पादों की खरीद	४९६
१५६.	परिवहन विकास	४९६
१६२.	भारी माल डिब्बा बनाने का कारखाना	४९६
१६३.	चीनी का कारखाना-मूल्य	४९७
१६४.	चीनी के सन्यन्त्रों के लिये विशिष्ट विवरण	४९७
१६५.	चीनी के कारखानों को ऋण	४९८
१६६.	दिल्ली परिवहन सहकारी समिति	४९८
१६८.	कलकत्ता में टेलीफोन सेवा	४९९
१६९.	किसानों को उर्वरक का सम्भरण	४९९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 7—Tuesday, February 18, 1964 / Magha 29, 1885 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	Subject	PAGE
150	Second Shipyard	473—74
151	Production of Sugar	475—78
152	Agricultural Production	478—80
153	Sugar Quota for U. P.	480—82
154	Avro-748 for I.A.C.	482—84
157	Agricultural Production Board	484—87
158	Freight on Export Goods	487—88
159	Distribution of Sugar	488—92
160	P. L. 480 Agreement	492—93
161	Special Stamps	494—95

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
155	Purchase of Agricultural Commodities	496
156	Transport Development	496
162	Heavy Wagon Building Plant	496
163	Ex-Factoy Price of Sugar	497
164	Specification for Sugar Plants	497
165	Loans to Sugar Mills	498
166	Delhi Co-operative Transport Society	498
168	Telephone Service in Calcutta	499
169	Supply of Fertilizers to Farmers	499

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या

१७०.	रेलवे में कोयले का प्रयोग	४९९—५००
१७१.	यूगोस्लाविया के कोयला ढोने के जहाज	५००
१७२.	फसलों को हुई हानि	५०१
१७३.	रात में खुले रहने वाले डाकखाने	५०१
१७४.	इंडोनेशिया में भारतीय जहाज के यात्रियों का फंस जाना	५०२
१७५.	कलकत्ते में टेलीफोन	५०२—०३
१७६.	चीनी के कारखानों को गन्ने का सम्भरण	५०३
१७७.	सहकारी शिक्षा निधि	५०३
१७८.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की "फाकर फ्रेंडशिप" सेवा	५०३—०४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२९१.	दिल्ली में राजघाट के पास यमुना पर पुल	५०४
२९२.	बख्तियारपुर में रेलवे पुल	५०५
२९३.	डाक विभाग के सुपरिन्टेंडेंट	५०५
२९४.	स्टेशनों पर जलशोधन सन्यन्त्र	५०५
२९५.	टेलीफोन कनेक्शन	५०५—०६
२९६.	डाक और तार कालोनी, बीकानेर	५०६
२९७.	वनरोपण	५०६
२९८.	अधिकारियों के लिये रेलवे सैलून	५०६—०७
२९९.	मर्गीपालन	५०७
३००.	बर्मा से आलू का आयात	५०७
३०१.	नाभा और ढबलन स्टेशनों के बीच विराम स्टेशन	५०७—०८
३०२.	होटल	५०८
०३.	दिल्ली में रिंग रोड पर बत्तियां	५०८—०९
३०४.	उत्तर-प्रदेश बिहार आसाम लिंक रोड	५०९
३०५.	पर्यटक केन्द्र	५०९—१०
३०६.	रोगों से प्रभावित धान की फसल	५१०
३०७.	दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें	५१०—११
३०८.	दिल्ली में टैक्सियां	५११

	Subject	Page
Unstarred		
Question Nos.		
170	Use of Coal in Railways	499—500
171	Yugoslav Coal Carriers	500
172	Damage caused to Crops	501
173	Night Post Offices	501
174	Indian Ship Passengers stranded in Indonesia	502
175	Telephone Connections in Calcutta	502—03
176	Supply of Sugarcane to Mills	503
177	Co-operative Education Fund	503
178	I.A.C. Fokker Friendship Aircraft Service.	503—04
291	Bridge on Yamuna near Rajghat Delhi	504
292	Railway Bridge at Bakhtiarpur	505
293	Postal Superintendents	505
294	Water Purification plants at Stations	505
295	Telephone Connections	505—06
296	P. & T. Colony, Bikaner	506
297	Afforestation.	506
298	Railway Saloons for Officials	506—07
299	Poultry Breeding	507
300	Import of Potatoes from Burma	507
301	Halt Station between Nabha and Dhablan Stations	507—08
302	Hotels	508
303	Lights on Ring Road in Delhi.	508—09
304	U. P. Bihar-Assam Link Road	509
305	Tourist Centres	509—10
306	Paddy Crop Affected by Diseases	510
307	Fair Price Shops in Delhi.	510—11
308	Taxis in Delhi	511

प्रश्नोंके लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०९.	रेलवे फाटक	५११
३१०.	विमान सेवायें	५११—१२
३११.	पोस्टल फार्म	५१२
३१२.	विल्लूपुरम-काटपाणी सैक्शन पर रेलवे दुर्घटना	५१२
३१३.	सन्तुलित भोजन	५१३
३१४.	तार	५१३
३१५.	सुवर्ण रेखा नदी पर पुल	५१३—१४
३१६.	कलकत्ता के इर्द गिर्द रिंग रेलवे	५१४
३१७.	केरल में रेलवे लाइनें	५१४
३१८.	तिलहनों का उत्पादन	५१४—१५
३१९.	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी	५१५
३२०.	बालाघाट में टेलीफोन सेवा	५१५—१६
३२१.	सड़क परिवहन—निगम	५१६
३२२.	केरल की चावल सम्बन्धी आवश्यकतायें	५१६—१७
३२३.	चीनी फैक्टरियों के लिये लाइसेंस	५१७—१८
३२४.	गाय के गोबर से गैस	५१८
३२५.	रेलवे रक्षा दल	५१८
३२६.	गन्ना उत्पादक	५१९
३२७.	दिल्ली-जोधपुर डकोटा सेवा	५१९
३२८.	विदेशी भाषाओं में पर्यटन विभाग का साहित्य	५१९—२०
३२९.	डाक टिकट	५२०
३३०.	बीमाशुदा लिफाफों से रुपया गायब हो जाना	५२०
३३१.	दिल्ली और बम्बई के बीच रेल की पटरी	५२१
३३२.	मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगना	५२१
३३३.	सीमेंट के स्लीपर	५२१—२२
३३४.	दिल्ली में यमुना के ऊपर नावों का पुल	५२२
३३५.	सहकारी कैन्टीनें	५२२—२३
३३६.	एयर इंडिया के किराये	५२३
३३७.	कांगड़ा घाटी का पुनर्मार्गरेखण	५२३

	Subject	Page
	Unstarred	
	Question Nos	
309	Level Crossings	511
310	Air Services	511—12
311	Postal Forms	512
312	Railway Accident on Villupuram-Katpadi Section	512
313	Balanced Diet	513
314	Telegrams	513
315	Bridge on River Subarnarekha	513—14
316	Ring Railway Around Calcutta	514
317	Railway Lines in Kerala	514
318	Production of Oilseeds	514—15
319	Singareni Collieries Company	515
320	Telephone Service in Balaghat	515—16
321	Road Transport Corportions	516
322	Rice Requirement of Kerala	516—17
323	Licences for Sugar Factories	517—18
324	Gas from Cow-dung	518
325	Railway Protection Force	518
326	Cane Growers	519
327	Delhi-Jodhpur Dakota Service	519
328	Tourist Literature in Foreign languages	519—20
329	Postage Stamps	520
330	Disappearance of Money from Insured Cover	520
331	Railway Track between Delhi and Bombay	521
332	Fire in Wagon	521
333	Cement Sleepers	521—22
334	Boat Bridge over Jamuna in Delhi	522
335	Cooperative Canteens	522—23
336	Air India Fares	523
337	Realignment of Kangra Valley	523

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३३८. पर्वतीय विकास सलाहकार बोर्ड ५२४

३३९. बड़े पत्तनो का यन्त्रीकरण . . . . ५२४—२५

३४०. उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्था . . . ५२५

३४१. उपभोक्ता सहकारी स्टोर ५२५

३४२. बख्तियारपुर-राजगीर रेलवे लाइन ५२६

३४३. जापानी विमान दल ५२६

३४४. रेलवे के सामान की चोरी . . . . ५२६—२७

३४५. भारत के रास्ते नेपाल-पाकिस्तान व्यापार मार्ग . . ५२७

३४६. सुपारी ५२७

३४७. मत्स्यपालन का विकास . . . . ५२७—२८

३४८. पंजाब में टेलीफोन ५२८

३४९. मैसूर में सहकारी चीनी फैक्टरियां ५२८

३५०. उर्वरक का आयात . . . . . ५२८—२९

३५१. कपास और तिलहनों की सघन खेती . . . ५३०

३५२. अवशिष्ट राशि का भुगतान ५३०

३५३. मद्रास राज्य में चीनी मिलें ५३०

३५५. रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ५३१

३५६. इम्फाल तथा लीलाबाड़ी में हवाई अड्डे . . . ५३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

शिलांग में कर्फ्यू लगाया जाना और सेना का बुलाया जाना . . ५३१—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५३२—३५

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३-६४—उपस्थापित . ५३५

राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक—उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ५३५—५५

श्रीमती रेणुका बड़कटकी . . . . ५३५—३७

आचार्य कृपालानी ५३७

श्रीमती गायत्री देवी . . . . . ५३७—३८

Written Answer—Contd.

	Subjet	Page
Unstarred Question Nos.		
338	Advisory Board for Hill Development	524
339	Mechanisation of Major Ports	524—25
340	Institute of Tropical Meteorology	525
341	Consumer Cooperative Stores	525
342	Bakhtiarpur-Rajgir Railway Line	526
343	Japanese Aircraft Team	526
344	Theft of Railway Materials	526—27
345	Nepal-Pak Trade Route through India	527
346	Arecanut	527
347	Development of Fisheries	527—28
348	Telephone Connections in Punjab	528
349	Co-operative Sugar Factories in Mysore	528
350	Import of Fertilisers	528—29
351	Intensive Cultivation of Cotton and Oilseeds	530
352	Payment of Arrears	530
353	Sugar Mills in Madras Government.	530
355	Quarters for Railway Employees	531
356	Airfields at Imphal and Lilabari	531

Re : Motions for Adjournment—

Alleged requisitioning of troops and curfew in Shillong . . 531—32

Papers laid on the Table . . . . . 532—35

Demands for Supplementary Grants (General), 1963-64—Presented 535

Motion of Thanks on address by the Vice President discharging the functions of the President. . . . . 535—55

Shrimati Renuka Barkataki . . . . . 535—37

Acharya Kripalani 537

Shrimati Gayatri Devi . . . . . 537—38

विषय	पृष्ठ
श्री व० बा० गांधी	५३८
श्री कु० शिवप्रसासन	५३९
श्री म० ला० द्विवेदी	५३९—४०
श्री कर्णीसिंहजी	५४०—४१
डा० च० भा० सिंह	५४२
श्री मलाइछामी	५४२—४३
श्री ह० प० चटर्जी	५४३—४५
श्री महेश दत्त मिश्र	५४५—४६
श्री सेझियान	५४६—४८
श्री श० ना० चतुर्वेदी	५४८—४९
डा० उ० मिश्र	५४९—५०
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	५५०—५२
श्री रामेश्वरानन्द	५५२—५३
श्री गोपालदत्त मैंगी	५५३—५४
श्री रावेलाल व्यास	५५४—५५

भारतीय वायु सेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य—

श्री यशवन्त राव चव्हाण	५५५—५६

Subject	Page
Shri V. B. Gandhi	538
Shri K. Sivappraghassan	539
Shri M. L. Dwivedi	539—40
Shri Karni Singhji	540—41
Shri Chandrabhan Singh	542
Shri M. Malaichami	542—43
Shri H. P. Chatterjee	543—45
Shri Mahesh Dutta Mishra	545—46
Shri Sezhiyan	546—48
Shri S. N. Chaturvedi	548—49
Dr. U. Misra	549—50
Shri Harish Chandra Mathur	550—52
Swami Rameshwaranand	552—53
Shri Gopal Datt Mengi	553—54
Shri Radhelal Vyas	554—55
Statement re : missing of I.A.F. aircraft.— Shri Y. B. Chavan.]	555—56

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, १८ फरवरी, १९६४/ २९ माघ, १८८५ [शक]

Tuesday, February 18, 1964/Magha 29, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष सभा के सामने नतमस्तक हो रहा होता है, तो सदस्यों को इधर उधर नहीं आना जाना चाहिये। कुछ शिष्टता तो रहनी ही चाहिये।

जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

\+

*१५०. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या परिवहन मंत्री दूसरे शिपयार्ड के विषय में २६ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या जापानी फर्म द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मित्सुबिशी फर्म का विशेषज्ञों तथा कार्यपालकों का दल गत नवम्बर में भारत आया था तथा उसने कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित विषयों पर सरकारी अधिकारियों से बातचीत की थी। बातचीत की समाप्ति के पश्चात् जापानी दल ने यह विचार व्यक्त किया कि सहयोग की शर्तें तय करने के लिये टोकियो में अग्रेतर विचार-विमर्श किया जाये जिसके लिये तिथि की सूचना वे देंगे। टोकियो में विचार-विमर्श करने के लिये तिथि की सूचना आज सुबह तक भी प्राप्त नहीं हुई थी। सभा के लिये प्रस्थान करते समय मुझे मित्सुबिशी फर्म से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि टोकियो में अग्रेतर बातचीत करने के लिये भारतीय दल को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुलाया जा रहा है।

श्री नि० रं० लास्कर : गत सत्र में इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक जापानी तथा भारतीय दल निश्चित रूप से इस विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे। मेरे विचार से उनके यह कहने का कुछ आधार था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह अब तक कैसे नहीं हुआ ?

श्री राज बहादुर : मुझे याद नहीं है कि मैंने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा था। परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने सब संभव प्रयत्न किये हैं तथा समय नहीं खोया है। इतना समय इसलिये लगा है क्योंकि जापानी दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की तकनीकी दृष्टि से भी जांच की जानी थी। इन महीनों के दौरान यही काम किया गया है।

श्री नि० रं० लास्कर : हम हमेशा से इसी प्रकार के उत्तर सुनते आ रहे हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय सहयोग के बारे में जापान तथा भारत के बीच कोई समझौता हो सका है अर्थात् इस बारे में कि जापान तथा भारत का सहयोग कितना कितना होगा ?

श्री राज बहादुर : इसी प्रकार की अनेक बातें हैं जिनके बारे में अन्तिम निश्चय किया जाना है।

श्री वारियर : परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य बातें, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बातें तथा वे बातें जिन पर अग्रेतर बातचीत आवश्यक है क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर देने का अर्थ है इस मामले की तकनीकी तथा वित्तीय अनेक बातों का ब्यौरा देना। जापानी दल ने शिपयार्ड के विकास के लिये एक क्रमगत कार्यक्रम तथा इसके द्वारा किये जाने वाले निर्माण की कुल मात्रा के बारे में प्रस्ताव रखा है। इन सब विषयों पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाना है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस बात का विश्वास है कि अन्ततोगत्वा सहयोग तथा अन्य तकनीकी विषयों के बारे में जापानियों के साथ समझौता हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : हमें ऐसी आशा है।

चीनी का उत्पादन

+

*१५१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जेबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ दिसम्बर, १९६३ को सभा में गन्ने के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा किये जाने से अब तक चीनी उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पिछले अनभव को ध्यान में रखते हुए अगली फसल के लिये गन्ने के मूल्य अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिये गये हैं; और

(ग) चीनी का रक्षित भण्डार बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) गत वर्ष इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में वर्ष १९६३–६४ में १६ दिसम्बर से ७ फरवरी तक चीनी के उत्पादन में ०.७२ लाख टन की वृद्धि हुई ।

(ख) अभी तक नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और जब तक उत्पादन हमारी आवश्यकता से काफी अधिक नहीं हो जाता, तब तक इस मामले पर स्पष्टत: गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता ।

Shri Parkash Vir Shastri : In view of the announcement of the Government that the target of production of sugar this year would be 33 lakh tons and for that matter restriction was imposed on gur in U.P., may I know whether this final target could be reached by the end of the year and if so, whether that restriction would also be removed ?

श्री अ० म० थामस : ३३ लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया गया था तथा प्रत्येक राज्य के लिये भी कोटे का आवंटन कर दिया गया है अर्थात् प्रत्येक राज्य को कितना उत्पादन करना है । लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हम ने अनेक उपाय किये थे तथा उनसे कुछ लाभ भी हुआ जैसा कि आपने देखा होगा कि ७ फरवरी, १९६४ को चीनी का उत्पादन १५.२७ लाख टन है जब कि १९६३ की इसी तिथि को वह १३.२३ लाख टन था । जैसा मैंने पिछले अवसर पर बताया है कि यह सीजन की अवधि तथा गुड़ के मूल्यों के स्तर पर निर्भर करता है । गुड़ लाने ले जाने

पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी, गुड़ क मूल्य बहुत अधिक हैं तथा गन्ना उत्पादक एक कारखाने के मुकाबले कहीं अधिक दे सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in reply to part (b) of the main question that prices of sugarcane for the next crop have not yet been fixed. The Minister of Food and Agriculture, Sardar Swaran Singh, had stated in the last session that in January a decision would be taken about fixing the prices of sugarcane for the next crop. May I know when a final decision would be taken in this regard so that it may have good effect on production next year?

श्री अ० म० थामस : वस्तुत: १९६४-६५ के लिये गन्ने के मूल्य की घोषणा कुछ ही दिनों में कर दी जायेगी।

श्री दाजी : क्या सरकार के पास इस कमी को पूरा करने के लिये कोई कायक्रम है तथा हमें चीनी की इस कमी को कब तक भुगतना पड़ेगा ?

श्री अ० म० थामस : हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों उपाय कर रहे हैं तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होने में कुछ समय लगेगा।

Shri Yashpal Singh : The damage to sugarcane crop by snowfull has resulted in shortage of Sugar by lakhs of maunds. From where is Government going to import sugar to make up this shortage ?

श्री अ० म० थामस : कदापि नहीं। हम आयात क्यों करें ? हम तो निर्यात करनाज चाहते हैं।

Shri Rameshwaranand : Centre has imposed no restriction on crushers. Restriction has been imposed on gur in U.P. In Karnal district no crusher is being allowed to operate. Sugarcane is beginning to go dry. Crushing is not being allowed at places from where sugarcane cannot come. Can the people grow sugarcane in future under such conditions ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : इन प्रतिबन्धों से गन्ने के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I would like to have the reply in Hindi.

अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह हिन्दी में कह सकते हैं ?

Shri Shinde : I will not be able to reply in Hindi.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या चीनी के कम सम्भरण के बारे में बिहार सरकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है ?

श्री अ० म० थामस : अधिकांश राज्य सरकारें अतिरिक्त कोटे की मांग कर रही हैं। परन्तु हमें चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रख कर ही चलना पड़ता है। इन मांगों की पूर्ति करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि जिस हिसाब से इस समय पिराई का कार्य चल रहा है उसको देखते हुए लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ? यह पता लगाने के लिये कि कितना गन्ना पिराई के लिये अभी पड़ा हुआ है, क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री अ० म० थामस : इस प्रश्न का उत्तर मेरे वरिष्ठ साथी पहिल दे चुके हैं तथा मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है।

श्री क० ना० तिवारी : पिराई का कार्य कब तक चलेगा तथा इस अवधि में कितना उत्पादन होने की आशा है ?

श्री अ० म० थामस : इस प्रश्न का उत्तर पहिले एक अवसर पर दिया जा चुका है ।

श्री विश्वनाथ राय : गुड़ तथा चीनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि गन्ने के मूल्य में जो वृद्धि की घोषणा की गई है, क्या वह प्रभावकारी सिद्ध हुई है और यदि हां तो कितना गन्ना गुड़ बनाने की अपेक्षा चीनी के कारखानों में गया हैं ?

श्री अ० म० थामस : खंडसारी, गुड़ तथा चीनी बनाने वालों को किये जाने वाले संभरण को विनियमित करने के लिये नियम १२५(ख) तथा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम को काम में लाया गया था । परन्तु इसके कोई विशेष परिणाम नहीं निकले । उत्पादक क्षेत्रों से गुड़ के आयत तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से ही कुछ लाभ निकल सका है । अन्यथा, गुड़ के भाव और भी अधिक होते ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकार सिंचाई की अधिक सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और क्या इस से गन्ने की मात्रा तथा किस्म में सुधार नहीं होगा ?

श्री शिन्दे : अवश्य, अधिक सिंचाई सुविधायें दी जाने से किस्म में सुधार होगा ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether the report of the Committee appointed by the Government, under its scheme to increase the production capacity of sugar factories with a view to boost up production of sugar, to increase the capacity of the factories by five lakh tons has been received.

श्री अ० म० थामस : विस्तार करने के सम्बन्ध में हम ने एक प्रकार से अस्थायी निर्णय कर लिये हैं । नये चीनी कारखाने स्थापित करने के बारे में दो या तीन सप्ताह में निर्णय कर लिया जायेगा और तभी हम ५ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता, विस्तार तथा नये कारखानों की स्थापना के बारे में घोषणा कर सकेंगे । यह घोषणा एक या दो महीनों में कर दी जायेगी ।

Shri Tulshidas Jadhav : What has been the increase in the supply of sugarcane after raising the rates, as compared to the supply prior to that, which has wiped out the existing scarcity of sugar?

श्री शिन्दे : हाल में प्राप्त गन्ने की फसल सम्बन्धी पूर्वानुमान से पता चलता है कि गन्ना कुछ अधिक बोया गया है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन मूल्यों के कारण ऐसा हुआ है ।

श्री वारियर : सरकार के पास इसका क्या जवाब है कि जब देश को देहली जसे कुछ भागों में चीनी बिना किसी खास कठिनाई के मिल रहा है, दक्षिण भारत में यह बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तथा इससे गुड़ का भाव भी चढ़ गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य की धारणा ठीक नहीं है । माननीय सदस्य को याद होगा कि देहली में चीनी की कमी होने के बारे में तो पिछले सत्र में भी शिकायत की गई थीं । बात यह है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां देश के अन्य भागों से तथा बाहर से बहुत व्यक्ति आते रहते हैं, अतः हमें दिल्ली का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Government is well aware that the consumption of gur among the rural population is quite heavy. In view of this, is Government considering to remove the restrictions imposed on gur in order to give protection to sugar?

श्री अ० म० थामस : जी, नहीं । प्रतिबन्ध को हटाने का हमारा बिलकुल भी विचार नहीं है ।

Shri Rameshwaranand : Then what will the villagers take ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह क्या है? मुझ बिना बताये ही वह एकदम खड़े हो जाते हैं ।

Shri Rameshwaranand : What will the villagers eat?

Mr. Speaker : What is required at the moment is patience.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : चीनी के भारी अभाव को देखते हुए तथा चीनी के रक्षित भंडार में वृद्धि करने के हेतु क्या मैं जान सकता हूं कि १९६० के बाद से चीनी के सहकारी कारखानों को लाइसेंस क्यों नहीं दिए गये हैं ? यदि ऐसा किया गया होता, तो चीनी का उत्पादन दुगना हो गया होता ।

श्री अ० म० थामस : लाइसेंस के बारे में मैं पहिले ही उत्तर दे चुका हूं । एक समय ऐसा आया था जब कि लाइसेंसों की मांग काफी पूरी हो गई थी तथा कुछ समय के लिये लाइसेंस देना बंद कर दिया गया था । हमने अब पुनः लाइसेंस देना प्रारम्भ कर दिया है । लगभग २०० प्रार्थनापत्र आय हुए हैं । इन प्रार्थना पत्रों की जांच पड़ताल करने में कुछ समय अवश्य लगेगा और मेरा विचार है कि एक मास के अन्दर हम आवश्यक घोषणा कर सकेंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी का वर्तमान अभाव चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता मे कमी के कारण नहीं है अपितु इसलिये है कि चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना नहीं मिल रहा है ।

Shri P. L. Barupal : Will the Food Minister be pleased to state how far it is true that production fell down in the Ganganagar Sugar Mill, Rajasthan, because the farmers did not give their sugarcane as they have not been supplied that much sugar as has been given to the people in cities?

श्री अ० म० थामस : वह इस प्रश्न से नहीं उत्पन्न होती ।

Shri Swaran Singh : It is true that price of sugar in Rajasthan has been high and the mills there have not been able to get as much sugarcane as they should have.

कृषि उत्पादन

\+

*१५२. **श्री हेम राज :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान पुनर्विलोकन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे): (क) और (ख) अभी दल ने अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है ।

श्री हेमराज : क्या प्रतिवेदन के पेश करने के लिये कोई लक्ष्य तिथि निश्चित की गई है तथा इस दल ने किन राज्यों का दौरा किया है ?

श्री शिन्दे : एक निर्देश दिया गया था कि वह मार्च १९६४ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन कर देंगे । दल ने कई संस्थाओं तथा भारत के राज्यों के कई अनुसंधान केंद्रों का दौरा किया था ।

श्री हेमराज : देश में खाद्यान्नों की इतनी अधिक कमी होने के कारण क्या सरकार इस कार्य में कुछ शीघ्रता करेगी ?

श्री शिन्दे : उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु इस समिति के प्रतिवेदन में शीघ्रता करने का वर्तमान निर्णयों पर प्रत्यक्षतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मैं बता चुका हूं कि प्रतिवेदन अगले महीने तक पेश कर दी जायेगी ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : समिति के निर्देशपद क्या हैं ?

श्री शिन्दे : निर्देशपद लम्बे चौड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो उनको सभा पटल पर रखा जा सकता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२३१३/६४]**

Shri Kashi Ram Gupta : I want to know whether the terms of reference of this team are regarding various kinds of foodgrains or some specific agricultural products only and whether sugar or sugarcane are included in them.

श्री शिन्दे : आशा है कि समिति भारत में अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगी तथा जहां तक हमें जानकारी है सभी कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान हो रहा है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Mr. Speaker, my question has not been answered. I want to know whether sugar is also included in them or not.

Shri Swaran Singh : Yes Sir, sugarcane is also there.

Shri Bibhuti Mishra : Has the Government directed the expets of various State Governments to assist this team by explaining as to what kind of land is there in their respective state, what crops are grown etc. ?

श्री शिन्दे : समिति समस्त भारत में विशषज्ञों तथा कृषि शास्त्रियों का परामर्श लेगी । भूमि के तत्वों के समन्वय के अनुसंधान का प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर समिति अवश्य जांच करेगी ।

श्रीमती सरोजिनी महिषी : क्या गत १५ वर्षों में देश में अनुसंधान कार्यों के समन्वय के लिये यही पहली समिति नियुक्त की गयी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : जी नहीं । पहले भी दो समितियों ने इस समस्या पर विचार किया था ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस समिति ने भी भूमि के कटाव के प्रश्न पर तथा भूमि की उर्वरता आदि मामलों पर विचार किया था ?

श्री शिन्दे : समिति को प्रत्यक्षत : इन मामलों पर विचार नहीं करना था ।

Shri Tulshidas Jadhav : I want to know whether there is any member in this Committee who is himself an agriculturist.

श्री शिन्दे : समिति के प्रधान एक विद्वान विशेषज्ञ हैं। समिति में भारत तथा विदेशों दोनों के विशेषज्ञ हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है तथा क्या वह समिति भूमि के तत्वों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्यों का समन्वय करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री अ० म० थामस : इस सम्बन्ध में मेरे साथी बता चुके हैं कि यह समिति अक्तूबर, १९६३ में नियुक्त को गई थी ? तथा आशा है कि यह अपना प्रतिवेदन मार्च १९६४ तक पेश कर देगी। आपके आदेशानुसार निर्देश पद सभा पटल पर रखे जा चुके हैं इसलिए ये सभी बातें उस में से देखी जा सकती हैं ।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : क्या समिति के सदस्य गैर सरकारी व्यक्ति तथा किसानों के प्रतिनिधि भी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बताया जा चुका है ।

श्री विश्वनाथ राय : राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहले नियुक्त की गई दो अन्य समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं ?

श्री अ० म० थामस : एक समिति १९५१ में तथा दूसरी १९५९ में नियुक्त की गई थी। वे सभी भारतीय तथा अमरीकी दल थे। उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया था और आवश्यक उपाय किए गये

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती यशोदा रेड्डी ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं लगभग वैसा ही प्रश्न पूछना चाहती थी जैसा कि अभी पूछा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उत्तर प्रदेश के लिये चीनी का अभ्यंश

\+

*१५३. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :

खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को चीनी का पर्याप्त अभ्यंश नहीं दिया जाता है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को किस आधार पर चीनी आवंटित की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) ६ महीने पहले नियंत्रण, जो जुलाई १९५८ से सितम्बर, १९६१ में कारखानों से राज्यों द्वारा उठाई गई चीनी की मात्रा तथा चीनी की उपलब्धता के बारे में चीनी का मासिक कोटा निश्चित किया गया है ।

Shri Vishram Prasad : How far the scarcity of sugar in U.P. has been kept in consideration while allotting the present sugar quota to that State ?

श्री शिन्दे : जैसा कि उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है नियंत्रण अवधि से छः महीनों में संबंधित राज्यों द्वारा उठाई गई मात्रा के आधार पर कोटा निश्चित किया गया है। उस समय संभरण स्थित इतनी खराब नहीं थी उस समय राज्य जितना मांगते थे उनको उतनी चीनी दे दी जाती थी। उस आधार पर वर्तमान कोटा निश्चित किया जा रहा है। परन्तु जैसा कि सब को ज्ञात है इस समय चीनी की स्थिति बड़ी खराब है तथा प्रत्येक राज्य अपने कोटे से ज्यादा चीनी मांग रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को उनकी मांग के अनुसार चीनी देना संभव नहीं है।

Shri Bade : Is it a fact that some parties had staged *Satyagraha* in Madhya Pradesh for getting sugar on the eve of Diwali? Is it also a fact that Madhya Pradesh is given lesser quota than Gujarat while the increase in population has been greater in Madhya Pradesh? Why are efforts not being made or have been made by the Govt. to pay attention to it and increase their quota ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मध्य प्रदेश में १२००० टन तथा गुजरात को २१,००० टन चीनी दी गई है। अब इस कोटे को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

Shri Rameshwaranand : May I submit.....

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Rameshwaranand : Kindly listen my submission.

Mr. Speaker : Please wait.

Shri Rameshwaranand : I will wait but you must listen my submission. Questions asked in Hindi are replied in English even though Sardar Swaran Singh knows Hindi very well and he is present here at this time. It means that we do not want to use Hindi at all.

Shri Bade : He has not followed my question in Hindi.

Shri Rameshwaranand : Why does he not reply in Hindi when he follows the question?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार उन राज्यों जहां पर महत्वपूर्ण उप-चुनाव हो रहा है जैसा कि पंजाब के अमृतसर जिले के पट्टी में हो रहा है, में चीनी का पर्याप्त अतिरिक्त आवंटन अनिवार्यतः करती है ?

श्री अ० म० थामस : हम इस आधार पर कोई आवंटन नहीं करते हैं।

श्री रा० गि० दुबे : क्या विभिन्न राज्यों को कोटा आवंटन करते समय सरकार चीनी के उत्पादन तथा राज्य की जनसंख्या का ध्यान रखती है ?

श्री अ० म० थामस : जी नहीं। यदि ऐसा किया जाये तो उत्तर प्रदेश को उसकी पूरी आवश्यकतानुसार चीनी मिलनी चाहिये।

Shri P. L. Barupal : Had some special quota been given to Rajasthan in October and November, if so, how much?

श्री अ० म० थामस : जी हां। गत दो महीनों में विशेष कोटा दिया गया है क्या इस महीन भी नीचे लिखे अनुसार कोटा दिया गया है :—

राजस्थान—१००० टन, बिहार—१००० टन, उत्तर प्रदेश—१५०० टन, आन्ध्र प्रदेश—१००० टन, महाराष्ट्र—१००० टन।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने राजस्थान के बारे मे पूछा था ।

श्री अ० म० थामस : राजस्थान को १००० टन चीनी दी गई है ।

Shri Kamalnayan Bajaj : May I know whether the hon. Minister met Acharya Vinoba Bhave recently and if so, are their discussions likely to have some effect on Government's policy regarding distribution and production of sugar? Can he give some information in this connection?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) : Yes, Sir;I met Acharya Vinoba Bhave because he was worried that people who make gur in U.P. do not probably get the proper price. I think he was satisfied when I submitted that these days the farmers in U.P. get a little more for sugarcane which is used for gur and they earn more this way than if they were to give it to the mills.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एवरो—७४८ की खरीद

\+

*१५४. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन मन्त्री १६ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कानपुर के वायुयान निर्माण, डिपो से खरीदे जाने वाले एवरो–७४८ विमानों की संख्या के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने एवरो ७४८ विमानों की अपनी आवश्यकता का अभी पूरा निर्धारण नहीं किया है ।

Shri Yashpal Singh : What is the use of having a lengthy procedure when this Government believes in coopratives ? Why is this factory not handed over to the Transport Department itself?

Mr. Speaker : It is altogether a different question. In the beginning they were going to purchase but now they are going to hand over.

Shri Yashpal Singh : Then, I will ask another question. When will this work be completed?

Shri Mohiuddin : The purchase of planes is a continuous process. Decision cannot be taken at any one time..............

Mr. Speaker : It will next be completed; it will continue.

Shri Yashpal Singh : How many have been taken so far ?

Shri Mohiuddin : So far the Corporation has asked for at least one plane so that training may be given to the pilots and an idea could be had of the difficulties experienced in carrying passengers. I hope we shall put in use one plane and decision about further requirements would be taken shortly.

श्री रंगा : इंडिया एयरलाइन्स को यह निर्णय लेने में कि ये विमान खरीदे जाने योग्य हैं इतना समय क्यों लगा उनको अन्य प्रकार के निर्णय जैसे कितने विमान तथा कब खरीदने हैं लेने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं समझता हूं कि निर्धारण के बारे में कुछ गलतफहमी है इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने नमूनों की जांच करने के बाद एवरो ७४८ (श्रंखला २) मान्यता दी है जिसका उत्पादन १९६३ में आरम्भ हुआ था इस प्रकार निर्णय लेने में निगम को अधिक समय नहीं लगा है। मैं समझता हूं कि कितने खरीदे जायेंगे इसका निर्णय करने में भी अधिक समय नहीं लगेगा ।

Shri Shashi Ranjan : I want to make one submission. It is said about all the problems presented or questions asked here that the things would be done in the near future or they are under consideration. Are there no directions issued to them to tell by what specific time a specific thing would be done because no work can be completed without fixing any time or date ?

Mr. Speaker : The Government is of your own party and why do you not.....

श्री त्यागी : सरकार तो लगातार चलती रहती है ।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमने कैरवैल विमानों को हाल में ही चलाना शरू किया है । हमें यातायात ढांचे का अध्ययन करना है । उस यातायात के आधार पर हमें आवश्यकता का निर्धारण करना है तथा वही खरीदारी करनी है जो इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को सफलतापूर्वक तथा दक्षता से चलाने में लाभकारी सिद्ध हो । एवरो–७४८ के बारे में हमने कहा है कि हम द्वितीय माला चलाने जा रहे हैं । एक बार संख्या भी बताई गई थी। परन्तु वह यातायात आंकड़ों पर आधारित थी । हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि वह स्थायी आवश्यकता थी। हमें समय समय पर यातायात का भी निर्धारण करना होता है ।

Shri Yashpal Singh : What would be the cost of one plane and how does it compare with the cost of foreign planes ?

Shri Mohiuddin : The cost of the plane has not yet been estimated because the manufacturers have not yet quoted the final price.

श्री जोकीम अल्वा: माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा ठीक है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भारतीय उत्पादन के लिए एक इशारा दे सकती है । भारतीय उत्पादन का विचार इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अधिकारियों के मस्तिष्क में आना चाहिए था ।

श्री महीउद्दीन: यह ७४८ कार्यक्रम प्रथमत: इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के परामर्श से निश्चित किया गया था। जब कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था तब इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कुछ प्रतिनिधि भी समिति में थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वरिष्ठ मंत्री की बात सुनने के बाद क्या सभा यह समझे कि सरकार ने बाद में यह ठीक समझा कि एवरो ७४८ का उत्पादन करे अथवा केवल संख्या का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री राज बहादुर : केवल संख्या का प्रश्न विचाराधीन है । चुनाव के बारे में तो दोबारा विचार ही नहीं किया गया ।

कृषि उत्पादन बोर्ड

\+

†*१५७. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नरसिम्हारेड्डी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६३ तक कृषि उत्पादन बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) बोर्ड द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) अब तक तीन बैठकें हुई हैं । नवम्बर, १९६३, दिसम्बर, १९६३, तथा जनवरी, १९६४ ।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादन बोर्ड ने कोई विशिष्टि सिफारिश नहीं की है परन्तु कृषि उत्पादन के सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया है तथा राज्यो को निम्न बातों के सम्बन्ध में बताया है :

(१) कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवंटित निधि का पूरा उपयोग;

(२) बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा बनाई गई सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग ।

(३) कृषि उत्पादन कार्यक्रम की शीघ्र क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध ।

(४) सघन कृषि का कार्यक्रम ।

(५) कृषि कार्यों के लिए सीमेंट, लोहा तथा इस्पात का पर्याप्त सम्भरण ।

(६) कृषि चरण का पर्याप्त तथा सम्बन्ध सम्भरण ।

इन मामलों पर मुख्य मन्त्री तथा राज्य मन्त्रियों में चार केन्द्रीय बैठकों में बातचीत हुई थी ।

राज्य सरकारें कृषि उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

Shri Yashpal Singh : Has this Board made any such recommendation that the main reason of shortage is that the profiteers purchase food grains from the farmers at half rates and are selling at double the price and whether it has also recommended the ways to put an end to profiteering?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) : I may tell the hon. Member that this Board has been constituted not to make recommendations but to take decisions and implement them. Representatives of various Ministries are there in the Board and whatever decision is arrived at is implemented. The question of prices is very comprehensive. Government has given it much thought and we will have to follow a middle way so that the cultivators may get the proper price and the consumers are also not heavily charged.

Shri Yashpal Singh : When will Government finally decide about setting up the proposed Price Stabilisation Board?

Shri Swaran Singh : It was felt that this work should be done by the Ministry itself. It was, therefore, not considered very essential to have this Board.

Shri Vishram Prasad : It has first now been stated by the hon. Minister that the Board has made recommendations about irrigation potentialities. Complete irrigation has been done by tubewells but I want to know how Government propose to tackle the problem of excessive charges being received from the farmers.

Shri Swaran Singh : Both these problems have been thoroughly considered and State Govts. have paid special attention to them. The situation has now some what improved.

श्री कपूर सिंह : क्या इस बोर्ड ने विश्व की इस राय की ओर भी ध्यान दिया है कि खेतों का स्वामित्व किसानों का होने पर कृषि उत्पादन अधिक हो जाता है तथा यदि हां, तो उनका इसके बारे में क्या सुझाव है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इसका प्रश्न में उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बात की ओर किस रूप में ध्यान दिया जा सकता है । परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध मे मतैक्य नहीं है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Has this Board considered this aspect also that rural electricity scheme should be launched in those areas as soon as possible where irrigation is done by wells so that production may be increased there in full capacity?

Shri Swaran Singh : Yes, Sir, it has been considered.

Shri Gulshan: Has this fact been brought to the notice of the Board that it is highly necessary to make up the shortage of foodgrains caused as a result of crops damaged by frost and whether it would be considered?

Shri Swaran Singh : Yes Sir, this would be considered by the state Governments.

Shri Rameshwaranand : I want to know whether this Board has ever recommended that attempt should be made to control floods in those areas where cultivable land has been rendered completely unfit for cultivation due to floods in the rivers in those areas.

Shri Swaran Singh : It has not yet been much discussed in the Board but the Ministry of Irrigation and Power and departments of the state Governments are thoroughly examining this matter.

श्री वारियर : क्या जल उपकर तथा सुधार कर, में किसानों द्वारा सिंचाई के पानी का प्रयोग करने के बारे में बाधक रहे हैं यह भी बोर्ड द्वारा विचार किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करने में जल कर बाधक हुआ है। परन्तु यह सच है कि जब कोई नया क्षेत्र नहरी सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाता है तब किसान उसका प्रयोग करने के लिए अपने को उसके अनुरूप बनाने में कुछ समय अवश्य लेता है।

Shri P.L. Barupal : May I know from the hon. Minister whether your Board is also considering.....

Mr. Speaker: I have no Board as such; please do not associate my name.

Shr P. L. Barupal : Is the Board considering to bring down the price of foodgrains which has gone up from Rs. 20 to Rs. 30 per maund?

Shri Swaran Singh : Yes Sir, it is true that the prices of wheat have considerably gone up in these days. But I must add that these days wheat is being given to the people from Govt. stocks in a huge quantity at very proper rates and during the last one month Government has released about 4½ lakh tons of wheat on a very low price. It is a fact that the market rates of wheat today are very high but the large quantity of wheat we are giving shall provide relief lakhs of consumers.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : केवल ४ ½ लाख टन गहूं दिए जाने पर भी किस प्रकार मूल्य इतने अधिक हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ किस्म के गेहूं के भाव इस कारण से कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन किस्मों के गेहूं की कमी है तथा उपभोक्ता उन किस्मों को लेना चाहते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि अब यह कठिनाई दूर कर दी गई है। ४ ½ लाख टन काफी मात्रा है। वर्तमान बाजार भाव ऊंचे होने पर लेनदेन तथा वास्तविक गेहूं की मात्रा से अधिक अन्तर नहीं था।

श्री त्यागी : क्या बोर्ड किसानों की आवश्यकता तथा प्रत्येक गांव में खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन की सम्भावनाओं का ग्रामवार सर्वेक्षण कर सकेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड है। जिसको अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण मामलों तथा निर्णयों की जानकारी है...

श्री त्यागी : क्या सर्वेक्षण नीति का मामला नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य को निसन्देह यह जानकारी होगी कि ग्राम स्तर कर्मचारियों तथा सामुदायिक विकास संगठनों को यह काम सौंपा गया है. . .

श्री त्यागी : पूर्ण असफलता ।

श्री स्वर्ण सिंह : . . . . कि वह देश के विभिन्न भागों में खण्ड क्षेत्रों की आवश्यकता का पता लगायें ।

श्री त्यागी : उनके निर्देश पद क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मन्त्री ने बताया है कि इस बोर्ड की कुछ सिफारिशों पर राज्य कृषि मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। कृषि मन्त्रियों ने किन बातों को एकमत से स्वीकार कर लिया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राज्य मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियों की क्षेत्रीय बैठक में लिये गये निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से होते हैं । विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने के मामले में उगाही को सुधारने के मामले में सभी निर्णय सर्वसम्मति से ही होते हैं ।

FREIGHT ON EXPORT GOODS

+

*158. { **Shri Bibhuti Mishra :**
　　　{ **Shri Mohan Swarup:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that with a view to encouraging exports, Railways have declared reduction of freight in respect of 65 items of engineering;

(*b*) if so, the extent of reduction;

(*c*) the date from which this reduction will take effect; and

(*d*) the amount of loss the Railways will sustain on this account?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) २५ प्रतिशत ।

(ग) १–१–१९६४ से ।

(घ) इस रियायत का अनुमानित मूल्य प्रतिवर्ष लगभग ७ लाख रुपये होगा ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know how the concession given by the Govt. has been contributory in promoting our trade.

श्री सें० वें० रामास्वामी : हमें कोई जानकारी नहीं है। यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

Shri Bibhuti Mishra: I want to know the extent of increase in our export through railways ever since the concession granted by the Government.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस रियायत के कारण लदान बढ़ गया है ?

श्री सें० वें० रामास्वामी : इतने शीघ्र यह नहीं बताया जा सकता ।

श्री अ० प्र० शर्मा : रेलवे को ७ लाख रुपये की हानि क्यों हुई है दर के कमी करने के क्या कारण हैं ?

श्री सें० वें० रामास्वामी : इसको नुकसान नहीं माना जा सकता है। रियायत देने से इसे अतिरिक्त यातायात मिलेगा जो अन्यथा नहीं मिलता।

चीनी का वितरण

\+

*१५९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जेधे :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम हरख यादव :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी वितरण के लिये केन्द्र ने राज्य सरकारों को कोई सलाह दी है ;

(ख) क्या पिछले चार महीनों में कुप्रशासन तथा मुनाफाखोरी के गम्भीर मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि वितरण के मामले में सरकार ने क्या दिलचस्पी ली है और क्या वे इसके दोषों को देख सके हैं और इन दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : हमने राज्य सरकारों को सामान्य हिदायतें दी हैं कि वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिये। स्वभावत: ही राज्य सरकारें इस मामले के ब्योरों पर बिचार करेंगी। हमने उनसे कहा है कि वे कारखाने के मूल्य में परिवहन व्यय को जोड़कर उसके आधार पर थोक मूल्य निर्धारित करें। हमने उनसे यह भी कहा है कि वे उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से वितरण की एक पद्धति प्रारम्भ करें, आकस्मिक जांच की व्यवस्था करें और थोक तथा फुटकर विक्रय के दोनों ही क्षेत्रों में सहकारी समितियों को पर्याप्त अवसर हैं। हमने उनसे यह भी कहा है कि वे फुटकर विक्रेताओं तथा बड़े उपभोक्ताओं के बीच सम्बंध स्थापित करें और चीनी के व्यापारियों से चीनी के मूल्यों को प्रदर्शित करने को कहें। ये सब हिदायतें विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि बाजार में चीनी दो मूल्यों पर मिलती है, एक तो वह है जिसे कि नियंत्रित मूल्य के नाम से कहा जाता है और दूसरा है निर्बाध बाजार मूल्य अथवा चोर बाजारी का मूल्य, जोकि बम्बई में २ रुपया प्रति किलो से लेकर राजस्थान में

४ रुपया प्रति किलो तक का है। निर्बाध बाजार में इस समय कितनी चीनी है, वह कहां से आती है और क्या सरकार इस स्थिति से सहमत है ?

श्री अ० म० थामस : इस प्रश्न का पहले भी एक बार मैंने उत्तर दिया था। वास्तव में, जो चीनी हम निकालते हैं उसका अधिकांश भाग सीधा उपभोक्ताओं को मिलता है ? परन्तु फिर उसका थोड़ा सा भाग वास्तव में चोर बाजार में भी चला जाता है। परन्तु ऐसा तो होना ही है क्योंकि, उद हरणार्थ जब चीनी का वितरण पहचान पत्रों के आधार पर किया जाता है तो जिन लोगों को वास्तव में चीनी की आवश्यकता नहीं है वे भी उसे ले सकते हैं और उसे दूसरे उपभोक्ताओं को दे सकते हैं, क्योंकि चीनी की एक आम कमी तो है ही। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि वास्तव में, इस बात के अतिरिक्त, अनेक विवरणों से हमको जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि लगभग ८० प्रतिशत चीनी का वितरण उचित माध्यमों से किया जाता है और वह सीधी उपभोक्ताओं को मिलती है। शेष २० प्रतिशत के सम्बंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता और जितनी भी सावधानी बरती जा रही है उससे भी इन दोषों को दूर नहीं किया जा सकता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री इस बात को मानते हैं कि चीनी २ रुपये प्रति किलो से ले कर ४ रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है और क्या सरकार इससे सहमत है कि ऐसा ही होता रहे ?

श्री अ० म० थामस : ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमको यह समाचार तो मिले हैं कि यह २ रुपये प्रति किलो के भाव पर बेची जाती है परन्तु चार रुपये प्रति किलो के भाव पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसे दुबारा न पूछते तो बात तय हो गई होती। अब उन्होंने इसका खंडन कर दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहता।

श्री रा० गि० दुबे : वितरण प्रणाली की सफलता को जानने के उद्देश्य से क्या सरकार ने किसी विशेष क्षेत्र में उचित मूल्य वाली दुकानों के मूल्यों की तुलना में निर्बाध बाजार के मध्य के स्तर को जानने का प्रयत्न किया है।

श्री अ० म० थामस : हमारे पास कुछ जानकारी है। उदाहरणार्थ, जिन मूल्यों को आप निर्बाध बाजार के मूल्य कहते हैं वे मूल्य और नियमित मूल्य मैसूर में लगभग एक ही जैसे हैं। गुजरात में, जहां कि चीनी का सम्भरण उनकी आवश्यकताओं की तुलना में पूर्णतः संतोषजनक है, चीनी की अधिक चोरबाजारी नहीं चल रही है। परन्तु उन कुछ राज्यों में जहां कि वास्तविक कमी है इन मूल्यों में असमानता है। हमको उसके बारे में समाचार मिले हैं और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वितरण प्रणाली मजबूत हो जाये।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has just stated that black-marketing is due to consumers. May I know whether Government is aware of the fact that some individuals take permits through the Govt. officials in supply offices and sell sugar in black market and Government has also a big hand in it ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) : I will request the hon. Member that if he has any such information he should pass it on either to the state Govt. or to me so that it could be investigated.

Shri Kapur Singh : He has said that Government is involved in it.

Shri Swaran Singh : I emphasise that I have no hand in it.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उसकी ढिलमिल अथवा अस्पष्ट नीति और हिदायतों के कारण विभिन्न राज्यों में कुछ एक सहकारी समितियों और सहकारी थोक स्टोरों को तो ५० प्रतिशत तक चीनी का कोटा वितरण के लिये दिया गया है जबकि अन्य बहुत सों को केवल ६ प्रतिशत अथवा उससे भी कम दिया गया है ?

श्री अ० म० थामस : यह निश्चय करना राज्य सरकारों का काम है । हमने यह हिदायतें दी हैं कि जहां कहीं भी सम्भव हो सके सहकारी समितियों को प्रोत्साहन तथा अधिमान दिया जाना चाहिये ।

Shri Tulsidas Jadhav : What is the reason that great inconvience is experienced in villages, particularly on holidays, in the distribution of sugar and sugar is not available at that time?

श्री अ० म० थामस : मुझे यह नहीं मालूम है, यदि कोई विशेष मामला मुझे बताया जायेगा तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री विश्वनाथ राय : जनता को चीनी मिलने में जो कठिनाईयां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर चीनी का व्यापार प्रारम्भ करने का है ।

श्री स्वर्ण सिंह : चीनी का वितरण तो बहुत ही नियंत्रित है ; अनेक वितरण केन्द्रों पर भी सतर्कतापूर्वक नियंत्रण रखा जाता है ; अनेक राज्यों में चीनी राशन कार्डों पर एक निश्चित मात्रा में दी जाती है और चीनी का व्यापार करने की तो बहुत ही कम गुंजाइश है; प्रश्न तो इस दुर्लभ पदार्थ के वितरण करने का है न कि उसमें व्यापार करने का ।

Shri M. L. Dwivedi : What is the reason that in several states, particularly in U.P., consumers have not got sugar for one month even though there is controlon sugar and it was there in stock only because the rate has not been made known from above?

Shri Swaran Singh : It is really surprising that sugar was not given to to the people though it remained in stock for a month and the Control rates had already been conveyed to them. I want to add another thing about U. P. and it is that this state is not only allotted the quota but besides this about 2 lakh tons of khandsari is also produced there on whose price there is no control. There should, therefore, be no scarcity of sugar there.

Shri M. L. Dwivedi : Would you enquire into the non-distribution of controlled sugar because rates were not made known?

Shri Swaran Singh : You give me the information and I will enquire.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली का अपना कोटा है और यदि हां, तो यहां पर क्या वितरण एजेन्सी है और दिल्ली में सहकारी सस्थाओं द्वारा कितनी चीनी का वितरण किया जा रहा है ?

श्री अ० म० थामस : दिल्ली का कोटा ६५०० टन प्रति माह का है और जहां कहीं भी सम्भव हो सका है हमने वितरण का कार्य सहकारी क्षेत्र को दिया है । हमने चीनी की फुटकर बिक्री वाली बहुत सी दुकानें भी खोली हैं और मैं नहीं समझता कि दिल्ली में चीनी के बारे में कोई कठिनाई है ?

Shri Radhelal Vyas : May I know whether the attention of the Govt. has been drawn to the fact that the distribution system of sugar is defective, specially about ration cards as has been referred to by you. It is not a ration

card, it is just a card for sugar on which one person can take one kilo of sugar daily. For that one has to stand in the queue. The result is that some people take sugar every day while others have to go without it even after standing in the queue for hours. Sugar thus taken goes to the black-market. Is some arrangement being made to check this?

Shri Swaran Singh : He has given more of information and not asked anything. If it is true then it is really bad and the Madhya Pradesh Govt....

Mr. Speaker : After giving the information he has added another three words as to what the Govt. is doing to check it.

Shri Swaran Singh : The system of distribution is in the hands of the State Government. I am surprised that one person takes sugar eight to ten times a day.....

Shri Radhelal Vyas : He does not take eight to ten times a day. But on that card one person takes one kilo of sugar every day even though there may be ten members at his home or he may he alone. He can get one kilo daily..

Shri Swaran Singh : I will bring this to the notice of the Madhya Pradesh Government because this seems to be improper.

श्री त्यागी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी कारखाने में उत्पादन की गई सारी ही चीनी को सरकार बिक्री के लिये ले लेती है अथवा उसका कुछ भाग कारखाने के पास खुले बाजार में खुली बिक्री करने के लिये छोड़ दिया जाता है?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय कारखाने के मालिकों के पास तनिक भी चीनी निर्बाध वितरण के लिये नहीं छोड़ी जाती क्योंकि यह विचार किया गया था कि यदि दो मूल्य रहने दिये जायें—एक तो नियंत्रित मूल्य और दूसरा निर्बाध बाजार मूल्य के नाम से कहा जाने वाला मूल्य—तो इससे बाजार में अव्यवस्था फैल जायेगी। **(अन्तर्बाधा)**

श्री हरि विष्णु कामत : आप इस विषय पर शीघ्र ही वाद-विवाद किये जाने की अनुमति दें।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में चीनी के वितरण के सम्बन्ध में एक समान प्रक्रिया अथवा नियम बनाने का सरकार का कोई विचार है, क्योंकि सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कार्ड नहीं दिये जाते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को राज्य सरकारों पर ही छोड़ना पसन्द करूंगा जो कि इस समस्या से अधिक परिचित हैं। यह सोचना उनका काम है कि जिस पदार्थ की कमी है उसके वितरण करने की सबसे अधिक न्यायसगत ढंग कौन सा है ?

Shri Rameshwaranand : Sir, I think all this discontentment is due to control. Is Government considering to lift the control?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

An hon. Member : The hon. Minister is going to reply.

Mr. Speaker : I have not allowed.

Shri Yashpal Singh : Why has extra quota of sugar not been allotted in the villages of 52 districts of U.P. on the eve of Id when extra quota is given on every festival?

Mr. Speaker : Let some new festival come now.

Shri P. L. Barupal : Sir, I may be given a chance to ask a question.

Mr. Speaker : Now it is too late. I have taken up the next question.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, injustice has been done to me. Although the hon. Minister was willing to give the reply you have not allowed him.

पी० एल० ४८० करार

\+

*१६०. **श्री वारियर :**
श्री वासु देवन नायर :
श्री महेश्वर नायर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० करार के अधीन खाद्यान्नों के आयात की समय सीमा बढ़ाने की भारत की प्रार्थना अमरीकी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो करार के अधीन आयात को कब तक पूरा किया जाना है ; और

(ग) पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत अब तक आयात किये गये खाद्यान्नों की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे): (क) और (ख). मई, १९६३ में जिस समय मई, १९६० के पी० एल० ४८० करार के संचालन का पुनर्विलोकन किया गया था तो उस समय अमरीकी सरकार से यह प्रार्थना की गई थी कि करार की समय सीमा को, जून, १९६४ से आगे जब कि यह करार समाप्त होता है, बढ़ाने के लिये सहमत हो जाये, जिससे कि गेहूं के नौभरण पूरे किये जा सकें। आशा है कि अगले कुछ ही महीनों में अमरीकी सरकार निर्णय ले लेगी ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० २३१५/६४]**

श्री वारियर : क्या पी० एल० ४८० के खाद्यान्नों के आयात के लिये समय-सीमा के बढ़ने से देश की खाद्य स्थिति पर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : निश्चय ही इससे बहुत सहायता मिलेगी । क्योंकि आयात किया हुआ अधिक गेहूं वितरण के लिये उपलब्ध होगा विशेष रूप से इस चालू वर्ष में जब कि यह समाचार मिले हैं कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में गेहूं की फसल खराब हो गई है ।

श्री वारियर : क्या इस करार के अनुसार सरकार अमरीकी खाद्यान्न के लिये उस मूल्य से अधिक मूल्य दे रही है जोकि इस समय भारत में चल रहा है और यदि हां, तो कुल कितना अन्तर है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं । यह बात सही नहीं है कि आयात किये जाने वाले गेहूं के लिये सरकार अधिक मूल्य दे रही है । वास्तव में तो यह गेहूं उपभोक्ताओं को एक बहुत ही रियायती

दर पर बेचा जा रहा है। कदाचित्, माननीय सदस्य उस क्षेत्र के नहीं हैं जहां कि गेहूं खाया जाता है और वह इस समस्या से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। (अन्तर्बाधा)

श्री वारियर : चावल के बारे में भी ।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि.... (अन्तर्बाधा)

श्री वारिययर : प्रश्न यह है कि क्या भारत में वर्तमान बाज़ार भाव की तुलना में हम क्रय मूल्य के रूप में अमरीकी सरकार को अधिक रुपया दे रहे हैं और यदि इन मूल्यों में अन्तर है तो इस करार के अनुसार, चालू वर्ष में कुल मिलाकर कितने रुपये का अन्तर पड़ेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि यह मामला नया नहीं है। इस पर अनेकों बार सदन में चर्चा की जा चुकी है। मेरी यह भावना है कि अमरीकी सरकार के साथ हमारा यह एक बहुत ही रियायती करार है जिससे कि इस मूल्य के लिए विदेशी मुद्रा दिये बगैर ही हमें खाद्यान्न मिल जाता है। उपभोक्ताओं को इस गेहूं अथवा चावल के विक्रय करने से जो रुपया मिलता है वह भी इस देश में ही रहता है और दोनों सरकारों के बीच पारस्परिक समझौते से हम विकास कार्यों के लिये भी उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्रय मूल्य यह है, बस इतनी सी बात है। (अन्तर्बाधा)

श्री रंगा : हमारे देश के उत्पादकों को अधिक मूल्य मिलना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ०म० थामस) : हम अधिक मूल्य नहीं दे रहे हैं; संसार के बाज़ार मूल्य पर हम खरीदारी कर रहे हैं। जब हम ने यह करार किया था उस समय से मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि रूस जैसे देशों और अन्य देशों ने भी खरीद की है; गेहूं का भी बाज़ार भाव थोड़ा अधिक हो गया है। यही कारण है कि हमें खाद्यान्न की वह पूरी मात्रा नहीं मिली जिसके लिये हम ने ठेका किया था--अर्थात्, १ करोड़ ६० लाख टन गेहूं और १० लाख टन चावल। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि हम संसार के बाज़ार भाव से अधिक मूल्य नहीं दे रहे हैं, परन्तु वे सदस्य तो यह जानना चाहते हैं कि क्या हम यहां के वर्तमान मूल्यों से अधिक मूल्य दे रहे हैं।

श्री अ० म० थामस : जी नहीं। वास्तव में, हम इस गेहूं का १४ रुपये प्रति मन की दर पर वितरण कर रहे हैं। हम जो अर्थ सहायता दे रहे हैं वह लगभग १ रुपया प्रति मन है। इस प्रकार, हम अधिक मूल्य नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

Shri Bibhuti Mishra: What is the actual reason for not importing foodgrains from the U.S. according to the programme? Is it that they have not sent or we have not asked for or we could not import due to the shortage of ships?

Shri Swaran Singh : The main reason was that we were importing according to our requirements and it was not essential to stock more than that. Now, of caurse, we have felt the necessity because of greater offtake these days. We shall, therefore, import a little more expeditiously.

विशेष डाक टिकट

+

*१६१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :

क्या डाक और तार मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाज सुधारकों और सुख्यात संगीतज्ञों की सूची तैयार कर ली गई है जिन के नाम पर डाक टिकटों की विशेष शृंखला जारी की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) सूची अभी तैयार की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. L. Dwivedy: Many a month has passed since reply was given to a previous question No 73. When will this list be finalised and which is the Committee considering this matter?

श्री भगवती : डाक टिकट संग्रह सलाहकार समिति इस मामले पर विचार कर रही है। ८ अक्टूबर, १९६३ को उनकी एक बैठक हुई थी। प्रत्येक सदस्य से कहा गया है कि वह दी गई सूची में से नामों का सुझाव दें। जब वह नामों का सुझाव दे देंगे तो अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। नामों को चुनने में उनको कुछ समय लगेगा।

Shri M. L. Dwivedy : Who are the persons in whose names stamps have been issued in 1964 so far and persons whose names are still under consideration?

श्री भगवती : १९६४ के लिये, हम १० विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय कर चुके हैं, जिसमें से ५ तो जारी किये भी जा चुके हैं। शेष यथासमय जारी किये जायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कोई ऐसा सुझाव अथवा प्रार्थना प्राप्त हुई है कि भारत, जिसका कि विश्वजनीन दृष्टिकोण है, लोकप्रिय नाटककार तथा कवि विलियम शेक्सपियर, जो कि केवल ब्रिटेन का एक गीतकार ही नहीं अपितु जिसे समस्त विश्व में सम्मान प्राप्त है, की स्मृति में कोई आयोजन करे और यदि हां, तो क्या सरकार ने आगामी अप्रैल में उनकी चारसौवीं वर्ष गांठ के अवसर पर उनकी स्मृति में कोई विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है ?

श्री भगवती : इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपको कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : उन्होंने बताया है कि यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है। अभी तक हमको ऐसा कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका सुझाव दे रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस पर विचार किया जायेगा ?

श्री अ० कु० सेन : जी, हां।

श्री रंगा : क्या आंध्र और दक्षिण भारत के वीर सालिगम का नाम उस सूची में है ? वह दक्षिण के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के रूप में सुप्रसिद्ध हैं।

श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य अपना सुझाव हम को भेज दें। हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा वीर सालिगम के नाम चुने गये नामों में हैं ?

श्री अ० कु० सेन : बात यह है कि अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है। जो भी नाम आये हैं वे डाक टिकट संग्रह सलाहकार समिति के पास भेजे जा रहे हैं। और भी जो नाम हमारे पास आयेंगे उन्हें भी इस समिति के पास भेज दिया जायेगा।

श्री प्र० के० देव : इस बात को देखते हुए कि उत्कल मणिगोपबन्धुदास के विशेष डाक टिकिट उसी समय जारी किये जब कि भुवनेश्वर का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, क्या हमें यह आश्वासन दिया जा सकता है कि भविष्य में डाक और तार विभाग की कार्यवाहियों को कभी भी किसी राजनैतिक दल की कार्यवाहियों के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य को इस मामले के प्रति एक ऐसा संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। वह समय इसलिये चुना गया था क्योंकि उस अवसर उस पूरे 'नगर का नाम उनके नाम पर रखा गया था।

श्री प्र० के० देव : यह कांग्रेस दल का एक मामला नहीं है, यह तो सभी दलों का मामला है।

Shri M. L. Dwivedy : Mr. Speaker, my question has not been fully answered. I had asked for the names. I wanted to know that out of these ten in whose names stamps have already been issued and in whose names they are yet to be issued. Names have not been given. I want that names should be told.

अध्यक्ष महोदय : क्या नाम तैयार हैं ?

Shri A. K. Sen : They have stated that names have not yet been finalised.

Shri M. L. Dwivedy : Names for 1964 have been finalised.

अध्यक्ष महोदय : नाम तैयार नहीं हैं। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि उत्पादों की खरीद

*१५५. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री घवन :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सिफारिश की है कि विपणन समितियां सीधे किसानों से ही कृषि उत्पाद खरीदें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **जी,** हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सिफारिश पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श में विचार किया जा रहा है ।

परिवहन विकास

*१५६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (आई० डी० ए०) कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया है तथा उसमें से कितना लिया गया है और प्रयोग में लाया जा चुका है ; और

(ग) अब तक विकास के किन विशिष्ट कार्यों को आरंभ किया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २३१४/६४]** ।

भारी माल डिब्बा बनाने का कारखाना

*१६२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी माल डिब्बा बनाने का कारखाना प्रस्तावित हल्दिया पत्तन के निकट स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) **जी, नहीं ।**

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का कारखाना- मूल्य

*१६३. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिणी राज्यों में चीनी के कारखाना-मूल्यों में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कारखाना मूल्यों में वद्धि की दर क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता मूल्य (फुटकर मूल्य) में क्या वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी के संयंत्रों के लिये विशिष्ट विवरण

*१६४. **श्री योगेन्द्र झा** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में चीनी के संयंत्रों के लिए विशिष्ट विवरण तैयार करने के लिए सरकार ने एक तकनीकी दल की नियुक्ति की है ;

(ख) क्या दल में कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों के और दल का वास्तविक गटन और निर्देश-पद क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर गये हुए एक अधिकारी को, भारत में चीनी की मशीनों के निर्माण के विकास सम्बन्धी कार्य में उसके अनुभव को देखते हुए, इस समिति में शामिल किया गया है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें समिति के गटन और उसके निर्देश-पद सम्बन्धी बातें बताई गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २३१६/६४]**

चीनी के कारखानों को ऋण

*१६५. श्री नाथ पाई :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी के उन कारखानों को, जो अपने उत्पादन का एक निश्चित अंश निर्यात कर रहे हैं, मशीनें आदि बदलने में और संयंत्रों के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए, रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों में, ऋण देने के लिये एक योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस पर कितनी राशि व्यय होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं ही उठते ।

DELHI COOPERATIVE TRANSPORT SOCIETY

*166. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Chuni Lal :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Transport Cooperative Society was set up in Delhi which has not yet started its work;

(b) whether it is also a fact that ten trucks purchased by the aforesaid society are lying in the Tis Hazari Court premises and are getting rusted;

(c) whether representations were received by Government in regard to the working of the society; and

(d) if so, the action taken by the Government in the matter?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The Honble Member is evidently referring to the Delhi Educated persons Cooperative Transport Society Limited. This Society was set up under the "pilot" scheme prepared by the Government of India for the setting up of transport cooperative societies for the educated unemployed and registered in the year 1960. It actually started functioning in November 1961 and continued to operate till November, 1963.

(b) The Society purchased 10 Tata Mercedes Benz truck chassis and got bodies built on 9 of them. The remaining one chassis is still lying with the dealer concerned. The nine vehicles have been parked at the Tis Hazari Court Compound since the 12th October, 1963.

(c) Yes.

(d) In view of the unsatisfactory financial position of the Society, the Delhi Administration decided that it should be wound up. Necessary orders in this regard were issued by them on the 27th November, 1963. Steps are being taken to complete the liquidation of the society as early as possible.

कलकत्ता में टेलीफोन सेवा

*१६८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में उन कुछ दिनों के दौरान जब वहां साम्प्रदायिक दंगे जोरों पर थे टेलीफोन बन्द रहे ; और

(ख) इस आवश्यक सेवा को २४ घंटे के भीतर पुन: चालू करने के लिए प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण थे । ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी, नहीं ; परन्तु इस अवधि में टेलीफोन काल्स की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य-भार बहुत ही अधिक रहा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को उर्वरक का संभरण

*१६९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को सहायता प्राप्त दरों[1] पर उर्वरक का संभरण करने के प्रस्ताव पर इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : केल्शियम एमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, जोकि अन्य उर्वरकों की तुलना में नये हैं, के उपयोग को अधिक लोकप्रिय बनाने के ध्येय से उनके मूल्य कम कर दिये गये हैं । केल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का पुंज मूल्य[2] ५ अक्टूबर, १९६२ से ३२ रुपये प्रति टन कम कर दिया गया था और यूरिया का १ जनवरी, १९६४ से १०० रुपये प्रति टन कम किया गया था ।

जहां तक सुपरफासफेट का सम्बन्ध है, उसके मूल्य को २५ प्रतिशत की सहायता दी जाती है जबकि वह राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी योजना के अधीन वितरित किया जाता है । अर्थ सहायता केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर दी जाती है । आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा के अतिरिक्त सभी राज्यों में यह योजना चल रही है । उन राज्य सरकारों ने यह सूचना दी है कि क्योंकि सुपरफासफेट किसानों में पहले ही से लोकप्रिय है इसलिए कोई अर्थसहायता देना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

रेलवे में कोयले का प्रयोग

*१७०. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक उत्पादक कोयला खान संस्था ने हाल में ही **रेलवे मंत्री** को ज्ञापन

[1]Subsidised rates.

[2]Pool price.

भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि घटिया किस्म के कोयले का अधिक प्रयोग किए जाने की संभावना की पुनः जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां ; ज्ञापन में बहुत सी बातें थीं जिन में से एक रेलवे में घटिया किस्म के कोयले का अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में थी ।

(ख) बढ़िया किस्म के कोयले की अपनी आवश्यकताओं के बदले में रेलवे में पहले ही से घटिया किस्म का कोयला भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, और रेलवे में घटिया किस्म के कोयले का और भी अधिक प्रयोग किये जाने की और कोई सम्भावना नहीं है ।

यूगोस्लाविया के कोयला ढोने के जहाज

*१७१. **श्री हेडा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यूगोस्लाविया के एक जहाज बनाने के कारखाने (शिप-यार्ड) को १३,४०० टन वाले चार कोयला ढोने के जहाजों के निर्माण तथा संभरण का आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक मिल जाने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार ने कोयला ढोने वाले जहाजों के संभरण के लिए कोई और करार भी किया है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ; भारतीयनौवहन निगम ने, जोकि पूर्णरूपेण सरकारी उपक्रम है, यूगोस्लाविया के एक जहाज बनाने के कारखाने को १३,४०० टन वाले चार कोयला ढोने के जहाजों के निर्माण के लिये आर्डर दिया है ।

(ख) निर्माण ठेके में इन जहाजों को बना कर देने का निम्नलिखित समय निर्धारित किया गया है :—

पहला जहाज	फरवरी, १९६६ के अन्त तक ।
दूसरा जहाज	मई, १९६६ के अन्त तक ।
तीसरा जहाज	अगस्त, १९६६ के अन्त तक ।
चौथा जहाज	अक्तूबर, १९६६ के अन्त तक ।

(ग) कोयला ढोने वाले जहाजों के सम्भरण के लिये सरकार ने और कोई करार नहीं किया है परन्तु उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र की एक नौवहन समवाय को बेल्जियन के एक जहाज बनाने वाले कारखाने के साथ कोयला ढोने के एक जहाज के निर्माण तथा सम्भरण का करार करने के लिये अनुमति दे दी है ।

Damage Caused to Crops

*172. Shri Brij Raj Singh :
Shri Bade :
Shri Maheshwar Naik :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extensive damage has been caused to standing crops due to the continuing frost brought about by the cold spell in Delhi, Punjab and Uttar Pradesh ;

(b) if so, the extent of damage caused ;

(c) whether the Central Government proposed to give some assistance to the States ; and

(d) if not, the steps proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) & (b). Reports received from State Governments indicate that there has been extensive damage to rabi crops in several districts of the Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh. It is not possible as yet, however, to make any quantitative estimate of the damage.

(c) & (d). Assistance as may be necessary will be given to States in accordance with the existing pattern of such assistance. So far no State has approached the Centre for assistance. Supplies of wheat are, however, being sent to areas where shortage of foodgrains is likely to arise.

रात में खुले रहने वाले डाकखाने

*१७३. श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग ने एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में रात में खुले रहने वाले और डाकखाने स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, प्रस्ताव को वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

इंडोनेशिया में भारतीय जहाज के यात्रियों का फंस जाना

*१७४. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री सरजू पांण्डेय :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री मणियंगाडन :
श्री सेझियान :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ दिसम्बर, १९६३ को एक भारतीय जहाज के यात्री इंडोनेशिया में फंस गये थे ;

(ख) यदि हां, तो घटना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। २४ दिसम्बर, १९६३ को एस० एस० 'मुहम्मदी' जहाज इंडोनेशिया के समुद्र में पी० नीपा रीफ पर उथले पानी में फंस गया था ।

(ख) और (ग). इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच इस समय जल परिवहन विभाग[1] बम्बई द्वारा की जा रही है और आगे यदि कोई कार्यवाही की जा सकती है तो वह जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही की जायेगी ।

कलकत्ते में टेलीफोन

*१७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते में नये टेलीफोन लगाने की स्थिति धीरे-धीरे और बिगड़ती जा रही है ;

(ख) १९६३ की तुलना में १९६४ के अन्त तक टेलीफोन के कनेक्शनों की मांग को देखते हुए उनके दिये जाने की अनुमानत : क्या स्थिति रहेगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन मंत्रणा समिति ने इस सम्भावना पर चिन्ता व्यक्त की है कि जब तक आमूल परिवर्तन नहीं किए जायेंगे तब तक नगर की टेलीफोन प्रणाली में गड़बड़ी होती रहेगी ।

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी, हां, प्रतीक्षक सूची बढ़ती ही जा रही है ।

(ख) १९६४ में लगभग ८,००० नये टेलीफोन कनेक्शन लगाये जाने की सम्भावना है जब कि अनुमान है कि इस वर्ष में १२,००० नये कनेक्शनों की मांग होगी ।

[1]Mercantile Marine Department.

(ग) जी, हां, जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार टेलीफोन प्रणाली का प्रसार करने के लिये विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है और टेलीफोन प्रणाली में गड़बड़ी होने की आशंका करने का कोई कारण नहीं है ।

चीनी के कारखानों को गन्ने का संभरण

*१७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २८ जनवरी, १९६४ को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय चीनी मिल संघ के प्रधान के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीनी के कारखानों को गन्ने का पर्याप्त संभरण कराते रहने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से कोई लाभ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) गुड़ और खांडसारी के जो ऊंचे मूल्य निरन्तर चल रहे हैं मुख्यत: उनके कारण, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सीमित प्रभाव हुआ है ।

सरकारी शिक्षा निधि

*१७७. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि सहकारी संस्थाओं के लाभों में से सहकारी शिक्षा निधि में अनिवार्य अंशदान के लिये सहकारी संस्था अधिनियम में उपबन्ध किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रति-क्रिया है ; और

(ग) कितने राज्यों ने अब तक इस पर सहमति प्रकट कर दी है तथा कितने राज्यों ने इस को अस्वीकार कर दिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) अनुकूल ।

(ग) १५ राज्यों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की 'फाकर फ्रेंडशिप' सेवा

*१७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए साल के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 'फाकर फ्रेंड-

शिप' विमानों ने बम्बई से सामान्य मार्गों पर उड़ाने नहीं कीं तथा उनके बजाय उस दिन उन मार्गों पर 'डकोटा' विमान भेजे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इस कारण हुआ था कि उस दिन 'फ्रेंडशिप' विमान के सभी विमान-चालकों तथा कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से बीमार होने की सूचना दे दी थी ;

(ग) इस कारण कितने यात्रियों को रुक जाना पड़ा ; और

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी हां, सिवाय आई० सी० १२३ सेवा के (बम्बई-अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली) जिस पर कि एक फ्रेंडशिप विमान चलता रहा था ।

(ख) फ्रेंडशिप विमानों के कुछ चालक अपने ड्यूटी के स्थान से बाहर थे अथवा अवकाश पर थे । बम्बई में जितने भी चालक थे उनमें से, बम्बई क्षेत्र के संचालन प्रबन्धक के अतिरिक्त जो कि एक योग्यता प्राप्त एफ–२७ कमान्डर तथा चालक हैं, शेष चालकों ने या तो बीमार होने की सूचना दे दी थी अथवा उनसे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका ।

(ग) जिन यात्रियों ने इन फ्रेंडशिप विमानों में यात्रा करने के लिये बम्बई से टिकट ली थीं, जो कि उड़ाये नहीं जा सके थे, उन्हें उसी दिन डकोटा विमानों द्वारा भेज दिया गया था । केवल चार यात्री शेष रह गए थे जिन में से दो ने अपनी टिकटें रद्द कर दी थीं क्योंकि वह डी० सी०–३ विमानों में यात्रा नहीं करना चाहते थे और शेष जिन दो को डकोटा विमानों में स्थान नहीं दिया जा सका था उन्हें दूसरे दिन भेज दिया गया था ।

(घ) जब कि यह स्पष्ट हो कि अनुपस्थिति कर्मचारियों की संयुक्त अथवा सामूहिक कार्य वाही के कारण है तो उस समय ऐसी आकस्मिक आपदाओं का सामना किया जा सके इसके लिये निगम के सेवा सम्बन्धी नियमों का संशोधन करने की सम्भावना की खोज की जा रही है ।

BRIDGE ON YAMUNA NEAR RAJGHAT, DELHI.

291. **SHRI SIDHESHWAR PRASAD :**
SHRI SUBODH HANSDA :

Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1344 on the 10th December, 1963 and state:

(*a*) whether the survey for the construction of a bridge on river Yamuna near Rajghat in Delhi has been completed; and

(*b*) if so, further progress made in the matter so far?

The Minister of shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): (*a*) & (*b*) Yes. The river survey work has since been completed by the Central Public Works Department. The drawings have been forwarded to the Hydraulic Research Station, Poona. The alignment and the design of the bridge will be decided on receipt of the final report from the Research Station.

RAILWAY BRIDGE AT BAKHTIARPUR

292. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1345 on the 10th December, 1963 and state:

(*a*) whether the scheme to construct a railway bridge at Bakhtiarpur has been accepted by the Government of Bihar; and

(*b*) if so, whether the construction of the bridge has been started?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (*a*) Not yet, Sir.

(*b*) Does not arise.

POSTAL SUPERINTENDENTS

293. **Shri Sidheshwar Prasad :** will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1346 on the 10th December, 1963 and state the progress since made in the integration of posts of Superintendents and Post Masters in the Postal Department?

The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagavati) : The recruitment rules for the combined cadre are under examination in the Posts & Telegraphs Board and when a decision is reached, they will be finalised in consultation with the Union Public Service Commission.

स्टेशनों पर जलशोधन संयंत्र[1]

२९४. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री १२ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे की नहर लूप लाइन पर ऐसे कौन से स्टेशन है जहां कि जलशोधन संयंत्र इस बीच में स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई प्रावस्थामाजित[2] कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जल शोधन संयंत्रों की व्यवस्था उत्तरी रेलवे की नहर लूप लाइन पर सूरतगढ़, सरूपसार, मोहन नगर, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर, श्रीकरनपुर और श्री गंगा नगर के स्टेशनों पर की गई हैं ।

(ख) जी हां ।

टेलीफोन कनेक्शन

२९५. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ तक राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी के लिये कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे ; और

(ख) इन कनेक्शनों को तेजी से लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक और तार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) बीकानेर—५०
गंगानगर—१७०

[1] Water Purification Plants. [2] Pased programme.

(ख) वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं और कार्य तेजी से किया जा रहा है ।

डाक और तार कालोनी, बीकानेर

२९६ **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **डाक और तार** मंत्री २ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर, राजस्थान में डाक और तार कालोनी में क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच में क्या प्रगति हुई है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): स्थान चुन लिया गया है और अर्जित किया जा रहा है ।

वनरोपण

२९७ **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाकायदा और व्यवस्थित वनरोपण के लिये कोई योजना अथवा रूपरेखा बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) वन राज्यों का विषय है और वनरोपण के लिये कार्यकारी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं ; और केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के मामले में यह कार्य संबंधित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है । आशा है कि "वन संसाधनों के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण" की क्रियान्विति होने पर राज्यों (पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मैसूर और महाराष्ट्र) में व्यवस्थित योजना की तैयारी के लिये आधार बन जायेगा ।

अधिकारियों के लिये रेलवे सैलून

२९८. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रेलवे अधिकारियों के लिये कुल कितने सैलून हैं ;

(ख) इन सैलूनों का कुल पूंजीगत परिव्यय कितना है ; और

(ग) इन सैलूनों को लिनन और क्राकरी देने का आवर्ती व्यय कितना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे अधिकारियों के लिये कोई सैलून नहीं हैं । हां, रेलवे अधिकारियों के इस्तेमाल के लिये जब कि वे दौरे पर होते हैं, निरीक्षण डिब्बे होते हैं । ऐसे निरीक्षण डिब्बों की संख्या लाइनवार निम्न है :—

बड़ी लाइन	४७७
मीटर लाइन	४२९
छोटी लाइन	४२
कुल	९४८

इन के अतिरिक्त अनेक पर्यटक कारें हैं जो विषय पर नियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक पार्टियों के लिये उपलब्ध हैं। ये डिब्बे रेलवे अधिकारियों द्वारा भी, जब वे दौरे पर होते हैं, उपलब्ध होने पर प्रयोग में लाये जाते हैं।

(ख) २,६५ लाख रु०

(ग) १,५६ हजार रु० प्रति वर्ष

मुर्गी पालन

२९९. श्री राम हरख यादव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने राजस्थान के कृषि कालिज को मुर्गीपालन में अनुसन्धान करने के लिये लगभग एक लाख डालर की राशि का पंचवर्षीय अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसन्धान कार्यक्रम का क्या ब्योरा है और अनुदान को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : जी, हां।

(ख) "मुर्गीपालन में सुधार के लिये "जर्म प्लाज्म' के संसाधनों को उपयोग करने की विभिन्न विधियों की प्रभावकारिता" पर अनुसन्धान करने के लिये पी० एल० ४८० प्रतिरूप निधि से राजस्थान कृषि कालिज को अमरीका सरकार ने पांच वर्षों में व्यय किये जाने वाले ५ लाख रू० के अनुदान का प्रस्ताव किया है। मामले पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा हो रही है।

बर्मा से आलू का आयात

३००. श्री ललित सेन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बर्मा से आलू का आयात किये जाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने भारत में पैदा किये गये आलू के विपणन पर इस आयात के प्रभाव पर विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गत वर्ष १०२ लाख रु० की विदेशी मुद्रा बर्मा से बीज-आलू के आयात के लिये दी गई, न कि भक्षणार्थ आलू केआयात के लिये क्यों कि देश में बढ़िया बीज-आलू का उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अभी भी पर्याप्त नहीं है।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी भी बीज-आलू में आत्मनिर्भर नहीं हैं यह प्रश्न नहीं उठता।

नाभा और ढबलन स्टेशनों के बीच विराम स्टेशन

३०१. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली डिवीजन में अम्बाला-धुरी शाखा लाइन पर नाभा और ढबलन के बीच नया हाल्ट स्टेशन खोलने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा और अनुमानित लागत क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) नाभा और ढबलन स्टेशनों के बीच एक नया हाल्ट स्टेशन खोलने का सुझाव प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

होटल

३०२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने होटल हैं जिनको विदेशों से सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) इस के क्या कारण हैं।

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अभी तक केवल एक पार्टी ने, जिसका नाम मैसर्स ईस्ट इन्डिया होटल्स लिमिटेड है, दिल्ली, बम्बई और आगरा प्रत्येक स्थान पर एक होटल स्थापित करने के लिये मैसर्स इन्टरकांटिनेंटल होटल कारपोरेशन आफ अमरीका से करार किया है। भारत सरकार ने इस सहयोग समझौते की शर्तों का समर्थन किया है जिस में यह व्यवस्था की गई है कि पहली अवस्था में नई दिल्ली होटल का निर्माण किया जाये और इसके सफलतापूर्वक निर्माण के पश्चात ही दूसरी अवस्था में बम्बई और आगरा में होटलों का निर्माण चालू किया जाय।

(ख) इस प्रकार के सहयोग की अनुमति के कारण निम्न हैं :—

(१) अन्य प्रगतिशील उद्योगों की भांति भारत में होटल व्यवसाय को तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है और ऐसे होटल से होटल व्यवसाय में नये तरीके आ जाते हैं जिनकी धीरे धीरे देश भर में नकल की जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था से अनेक लाभ होते हैं।

(२) यदि ऐसी कम्पनी से, जिसके कि बड़ी संख्या में होटल हों, जैसे कि इन्टरकांटिनेंटल अथवा हिलटन, समझौता किया जाय तो इसे भारत के होटलों का विश्व भर में प्रचार होगा जिसका अथ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय पर्यटन का प्रचार है।

दिल्ली में रिंग रोड पर बत्तियां

३०३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिफेंस कालोनी से ठीक धौला कुआ (दिल्ली) तक रिंग रोड पर बत्तियों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) ऐसी क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण अभी तक बत्तियों की व्यवस्था नहीं हो सकी ; और

(ग) दिल्ली में रिंग रोड के इस भाग पर पर्याप्त बत्तियों की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) से (ग). रिंग रोड को मुख्यत: तेज चलने वाली मोटर गाड़ियों के सीधे यातायात के लिये बनाया गया था। ये गाड़ियां अपनी बत्तियों के प्रकाश से चलती हैं। अत: सड़क पर कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई। स्थानीय यातायात समान्तर सेवा सड़को (सर्विस रोड्स) पर चलना था जो स्थानीय शासन को बनवानी थीं। इन सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जानी थी। तथापि, चूंकि अब तक सेवा सड़कें बनाना सम्भव नही हो सका है और जनता की ओर से सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये बराबर मांग रही है,इस बीच में यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन मुख्य रिंग रोड पर रोशनी की व्यवस्था करेगा। कार्य पर आने वाली लागत का अनुमान दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा लगाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश–बिहार–आसाम लिंक रोड

३०४. **श्री वारियर**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम को मिलाने वाली एक सामरिक महत्व की सीमा सड़क के निर्माण के लिये ७० करोड़ रु० की एक योजना सरकार के विचाराधीन रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना इस समय किस अवस्था में है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). शायद माननीय सदस्यों का तात्पर्य प्रस्तावित पार्श्विक सड़क से है जो कि उत्तर प्रदेश में बरेली को, बिहार और पश्चिमी बंगाल से गुजर कर आसाम मे आमिनगांव से मिलाने के अभिप्राय से बनाई जायेगी। इस परियोजना पर प्रारम्भिक रूप से विचार किया जा रहा है।

पर्यटक केन्द्र

३०५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन से संबंधित देश में कुछ स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). इस समय सरकार के सामने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन से संबंधित स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप मे विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों का औसत ठहराव लगभग १५ दिन है और इस छोटे से समय में वे ऐसे बड़े देश में केवल कुछ ही स्थानों का दौरा कर सकते हैं, विशेषत: उन स्थानों का जो कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और जहां कि हवाई जहाज जा सकते हैं और जहां पर कि आवास, परिवहन आदि की उचित सुविधायें हैं।

उपलब्ध समित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ चुने हुए केन्द्रों का, जहां कि पर्यटक बड़ी संख्या में आते रहे हैं दृढ़ रूप से विकास करने का निर्णय किया है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन से संबंधित स्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिये वे केवल देशी पर्यटकों के दृष्टिकोण से ही मुख्यत: महत्वपूर्ण समझे जा कसते हैं। देशी पर्यटको के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, यद्यपि केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारो को उन स्थानों में देशी पयटकों के लिये सुविधाओं के विकास की लागत का ५० प्रतिशत देती है जहां कि विदेशी पर्यटक भी जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकारों के कार्यक्रम में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन और कार्य से संबंधित विकास के किसी प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है।

रोगों से प्रभावित धान की फसल

३०६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि गत खरीफ ऋतु में राज्य भर में खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर धान मारी और रोग लगे ;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि फसलों को कितनी हानि पहुंची और इस का अन्तिम उपज पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में फसलों के संरक्षण के लिये कोई मार्गोपाय निकाले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं। जांच करने पर, तथापि उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर और बोलनगीर जिलों में धान मारी और रोगों के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का वायदा किया है। समाचार मिला है कि अन्य जिलों में इन रोगों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है।

दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें

३०७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी गेहूं, चावल और दालों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें खोली हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी दुकानें खोली गई हैं ; और

(ग) दुकानों को देने के लिये क्या कसौटी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आयात किए गए गेहूं की बिक्री की उचित मूल्य वाली दुकानों की संख्या हाल ही में पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है।

(ख) १२ फरवरी, १९६४ को ४८७ उचित मूल्य वाली दुकानें थीं।

(ग) उचित मूल्य वाली दुकानें देने के लिये इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं, दुकानों का आकार और स्थान और दुकानदारों की व्यापारिक अवस्था।

दिल्ली में टैक्सियां

३०८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों की हाल की हत्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार रात्रि के आठ बजे बाद टैक्सी ड्राइवरों द्वारा एक और व्यक्ति को साथ ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब निर्णय करने की आशा है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन वहनमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). ३० दिसम्बर, १९६३ को राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली ने यह निर्णय किया कि टैक्सी ड्राइवर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में रात्रि के आठ बजे और प्रातः पांच बजे के बीच और शेष के महीनों में रात्रि के ९ बजे और प्रातः के ५ बजे के बीच गाड़ी में एक परिचारक इस शर्त पर ले जा सकते हैं कि जब भी गाड़ी में परिचारक उपस्थित हो ३ से अधिक यात्री न ले जाए जायें।

रेलवे फाटक

३०९. **श्री कृष्ण पाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों पर गत वर्ष कितने रेलवे फाटक बनाए गए ;

(ख) इस पर कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में और रेलवे फाटक बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पांच।

(ख) २२,२८६.४८ रु० परन्तु द्वारपालों के लिए क्वार्टर अभी बनाए जाने हैं।

(ग) जी , हां ।

AIR SERVICES

310. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state;

(*a*) whether it is a fact that smaller cities are being linked by air services in India;

(*b*) if so, the cities which will be covered by the services; and

(*c*) the date from which such services will be introduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Bhopal and Raipur. In addition Nagpur has been connected by day service.

(*c*) 1st February, 1964.

Postal Forms

311. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that in all the Post Offices of Varanasi, Uttar Pradesh (Specially Kamachha, Sigra, Englishia Line City, Bengali Tola) there is a constant shortage of transfer of savings accounts forms, money orders forms, express delivery labels and forms for opening savings bank account;

(*b*) whether it is also a fact that the work is transacted in these Post Offices at a very slow speed and the employees attending the public lack courtesy; and

(*c*) if so, the steps Government propose to take to improve the conditions of those Post Offices?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (*a*) No Sir. There was however a temporary shortage of only one form for transfer of Savings Bank accounts. The shortage was remedied immediately it was noticed by sending a supply from neighbouring offices.

(*b*) No such complaint has been received.

(*c*) The question does not arise.

बिल्लूपुरम-काटपाडी सैक्शन पर रेलव दुर्घटना

३१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ दिसम्बर, १९६३ को दक्षिण रेलवे के बिल्लूपुरम काटपाडी सैक्शन पर वेलानंडल तथा टेडाक्काई स्टेशनों के बीच माल गाड़ी का एक भाग एक यात्री गाड़ी से टकरा गया तो कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दुर्घटना १४ दिसम्बर, १९६३ को हुई और परिणामतः एक व्यक्ति मर गया तथा नौ लोगों को चोट आई जिसमें एक को सख्त चोट आई ।

(ख) और (ग). रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त बंगलौर ने इस दुर्घटना के संबंध में अपनी संविहित जांच की है । उसकी अनन्तिम उपपत्ति यह है कि दुर्घटना का कारण यह था कि माल गाड़ी का उपकरण खराब हो गया था ।

संतुलित भोजन

३१३. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौष्टिक भोजन विभाग ने विविध आयु वर्गों के लिये सन्तुलित भोजन चार्ट बनाया है ; और

(ख) क्या इसका उन लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है, जो सन्तुलित भोजन के संबंध में अध्ययन करने के उत्सुक हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० यामस) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

तार

३१४. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्र के इन समाचारों पर गया है कि पंजाब राज्य के एक सैक्शन में ऐक्सप्रेस तथा प्रेस तारें भेजने में असाधारण विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को सुधारने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। एक मामले की जांच की गई है और कार्रवाई की गई है। अन्य मामलों की जांच हो रही है।

(ख) इस मामले पर डाक व तार बोर्ड द्वारा सेवा को सुधारने के लिए लगातार समीक्षा द्वारा पंजाब के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा लगातार जांच की जाती है।

सुवर्णरेखा नदी पर पुल

३१५. **श्री गो० महन्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ पर बालासोर जिले में सुवर्णरेखा नदी के ऊपर पुल बनाने का काम तीसरी योजना अवधि में आरम्भ किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). राजघाट के समीप सुवर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित पुल बालासोर खड़गपुर सड़क पर बनेगा, जो कि राज्य की सड़क है अतः पुल का निर्माण मुख्यतः उड़ीसा सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि राज्य सरकार

[श्री राज बहादुर]

ने हाल ही में इस परियोजना के लिए कुछ वित्तीय सहायता मांगी है जिसकी जांच भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

कलकत्ता के इर्द गिर्द रिंग रेलवे

३१६. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के इर्द-गिर्द एक रिंग रेलवे बनाने के संबंध में यदि निर्णय किया गया है तो क्या ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

केरल में रेलवे लाइनें

३१७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टे काट्टू :
श्री काप्पन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी योजना में आरम्भ किए जाने के लिये राज्य में किसी नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) इसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। चौथी योजना के लिए प्रस्ताव अभी नहीं मांगे गए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहनों का उत्पादन

३१८. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तिलहनों के निर्यात महत्व की दृष्टि से, देश में इनकी किस्म और उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कार्रवाई की जा रही है ; और

(ख) क्या इनके सुधार के लिये कोई गवेषणा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी, हां। समेकित तिलहन विकास योजनाएं सभी महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में चालू की गई हैं। इसके

अतिरिक्त, तिलहनों संबंधी पैकेज प्रोग्राम ९ राज्यों में आरम्भ की गई हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उर्वरकों, कृषि नाशक औषधों, पौधा संरक्षण उपकरणों तथा बीजों के लिये ऋणों और सहायता के रूप में तिलहन उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है।

वनस्पति तेलों और खली की शुद्धता तथा किस्म निर्धारण करने के लिये प्रादेशिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(ख) अधिक उपज तथा अधिक तेल वाली उत्तम किस्म बनाने के लिये और कृषि संबंधी उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करने तथा कीड़ों और बीमारियों के इलाज के उपाय मालूम करने के लिये छप्पन कृषि गवेषणा योजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

३१९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के प्रबन्धकों ने रेलवे प्रशासन से मंडामारी से रामकृष्णपुर कोयला खानों तक के लिये रेलवे साइडिंग की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब आरम्भ किया जाएगा ;

(ग) साइडिंग की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा कितने प्रतिशत लागत वहन की जाएगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) प्लान और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। कोलियरीज कम्पनी द्वारा प्लानों और प्राक्कलनों के स्वीकार हो जाने के पश्चात् और जब वे अपने हिस्से की राशि दे देंगे उसके पश्चात् रेलवे द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

(ग) और (घ). लागत के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि प्राक्कलनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

बालाघाट में टेलीफोन सेवा

३२०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या डाक और तार मंत्री बालाघाट में टेलीफोन सेवा के संबंध में १७ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दंडाधीश के निष्कर्ष तथा उनके बारे में अपना मत भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त सार क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो राज्य सरकार को कितनी बार इस मामले में शीघ्रता करने को कहा गया है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने एक ए० एस०आई० तथा स्टेशन अफसर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले मांगे हैं और उन के विरुद्ध विभाग जांच चल रही है । ए० एस० आई० को भी मूअत्तिल कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सड़क परिवहन निगम

३२१. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विविध राज्यों में सड़क परिवहन निगमों मे कितना धन लगाया है;

(ख) विविध राज्यों में सड़क परिवहन की गति किस ढंग से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है; और

(ग) पिछले दस वर्षों में उस पूंजी विनियोजन से सरकार को वार्षिक लाभ कितना हुआ है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आद्यतन केन्द्रीय सरकार द्वारा ११ राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में कुल १३,१४,७६,४८२ रुपये पूंजी लगाई गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की नीति है कि : (१) कभी सड़क यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का विचार किया जाता है, यह क्रम-बद्ध आधार पर की जानी चाहिये, और (२) राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रमों का प्रबन्ध सड़क परिवहन निगमों अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत स्थापित सड़क परिवहन निगमों द्वारा किया जाना चाहिये, जिस में केन्द्रीय सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा भाग लेती है । इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सड़क और रेल परिवहन के बीच उचित समन्वय रहे । चूंकि सड़क परिवहन के संबंध में कार्यपालिका प्राधिकार राज्य सरकार का होता है, उपरोक्त नीति को कार्यान्वित करने का काम उनको सौंप दिया गया है । तथापि उन राज्य परिवहन उपक्रमों के विस्तार कार्यक्रम के लिये साधारणतया कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती, जिनका प्रबंध विभागीय सार्थों के रूप में किया जाता है और उन कार्यक्रमों के लिये धन संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उसकी योजना के बाहर अपने साधनों से दिया जाता है ।

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित विनियोजन पर कुल लाभ २,८६,२४,८६६ रुपये ही समुची अवधि १९५२–५३ से १९६२–६३ तक की अवधि में वर्ष वार आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

केरल की चावल सम्बन्धी आवश्यकतायें

३२२. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६३ में केरल के खाद्य मंत्री की उनके साथ मुलाकात हुई थी,

(ख) क्या चावल के संबंध में केरल की आवश्यकताओं के बारे में उस बैठक में चर्चा की गई, और

(ग) क्या कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). केरल राज्य की चावल की आवश्यकता पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जाता है और केन्द्रीय आरक्षित भंडार से संभरण किया जाता है, राज्य के पास उपलब्ध स्टाक तथा अन्य अभावग्रस्त राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए । चावल राज्य में स्थित केन्द्रीय डिपुओं से केरल में सीधे उचित दामों की दुकानों को दिया जाता है और वितरण सारा साल चलता रहता है ।

चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस

३२३. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी फैक्टियों के नये लाइसेंसों की स्थिति पर पुनर्विचार करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों की वर्तमान उत्पादन सीमा को बढ़ाने के लाइसेंसों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन सदस्य हैं ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) नवीन फैक्टरियों की स्थापना तथा वर्तमान फैक्ट्रियों के विस्तार के संबंध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों की छानबीन करने के लिये एक अन्तर्विभागीय छानबीन समिति बनाई गई है ताकि खाद्य विभाग लाइसेंस देने वाली समिति को अपनी सिफारिशें भेज सके।

(ख) समिति के सदस्य ये हैं :—

१. संयुक्त सचिव (चीनी) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)	सभापति
२. मुख्य निदेशक चीनी तथा वनस्पति निदेशालय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	सदस्य
३. सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सहकार विभाग) का प्रतिनिधि	सदस्य
४. प्रविधिक विकास महानिदेशक का प्रतिनिधि	सदस्य
५. राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर का प्रतिनिधि	सदस्य
६. निदेशक (चीनी तकनीक) चीनी तथा वनस्पति निदेशालय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	सदस्य सचिव।

(ग) समिति को किसी निश्चित तिथि तक अपनी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिये होती, किंतु यह आशा की जाती है कि समिति की सिफारिशें शीघ्र ही पेश कर दी जाएंगी ।

Gas From Caw-Dung

324. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri N. R. Laskar :
Shri Maheswar Naik :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the country-wide progress made in the use of plant for producing gas from cow-dung;

(*b*) whether Central Government is considering the question of giving financial assistance to the farmers for such plants through the State Governments; and

(*c*) if so, the particulars thereof?

The Minister of Stae in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) to (*c*). A statement giving the required information is attached. **[Placed in Library See No. LT 2317/64].**

Railway Protection Force

325. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of thefts detected and quantity of goods so far recovered by the Railway Protection Force year-wise since its inception ;

(*b*) whether it is a fact that most of the Zonal Railways have detective dogs ; and

(*c*) if so, the amount being spent on them annually by the Railways ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Number of thefts of public property detected and value of property recovered from 1959 to 1963 are given in the attached statement ***[Placed in the Library. See No. LT 2318/64]***. It is not possible to give the quantity of goods recovered, as the materials recovered are of various shapes, sizes, weights and measures and they run into thousands on each Railway.

(*b*) Yes.

(*c*) The required information is given below :—

Railway	Annual expenditure (Approx.)
1. Southern	Rs. 11,000
2. North Eastern	Rs. 2,900
3. Northern	Rs. 2,875
4. Western	Rs. 13,890
5. Central	Rs. 9,219
6. South Eastern	Rs. 3,437

Cane Growers

326. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that cane growers are being paid less price than the prescribed one by sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar ; and

(*b*) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

दिल्ली-जोधपुर डकोटा सेवा

३२७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता आगरा और जयपुर, दिल्ली तथा जोधपुर के बीच एक दैनिक डकोटा सेवा आरंभ करने का अब निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि को आरंभ होगी, और

(ग) समय के बारे में क्या विवरण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) फरवरी, १९६४ से चालू होगी ।

(ग) समय अनुसूची इस प्रकार होगी :

दैनिक			दैनिक
०६३०	छू० दिल्ली	प०	१४३०
०७२५	प० आगरा	छू०	१३३५
०७४५	छू० आगरा	प०	१३१५
०८४५	प० जयपुर	छू०	१२१५
०९०५	छू० जोयपुर	प०	११५५
१०२०	प० जोधपुर	छू०	१०४०

Tourist Literature in Foreign languages

328. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(*a*) the Foreign languages other than English in which literatre of Tourist Department is avilable ;

(*b*) the foreign languages, besides English, with which the guides are conversant and how does the number of such guides compare to that of guides knowing English language ;

(*c*) the steps being taken to make available the literature in other languages besides English as also to train the guides ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (*a*) 23 guides and folders have been brought out by the Department of Tourism in French, 20 in German, 17 in Spanish and 12 in Italian. Only one folder giving information on Customs formalities etc., is available in Portuguese for distribution in Brazil. Literature in Russian, Japanese and Thai has also been brought out for specific purposes.

(*b*) Out of a total number of 228 guides who are on the approved list of the Department of Tourism and who are actively carrying on the work of guiding, only 29 are conversant with another foreign language besides English. Amongst these 17 are conversant with French, 3 with German, one with French and German, 4 with Spanish, one with Japanese, one with French and Italian, one with French, Spanish and Italian and one with German, Spanish, Italian and Arabic.

(*c*) (i) Literature in other languages is brought out as and when need arises. For instance the India Indexed Folder in Russian was brought out specially for distribution at the Indian Exhibition held in Moscow last year.

(ii) In order to ensure that foreign tourists speaking languages other than English may have services of trained guides available to them in their own language, preference is given to applicants conversant with foreign languages at the time of selection of guides for training courses.

Postage Stamps

329. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that much inconvenience was caused to the public in Kotah, Rajasthan from 4th December, 1963 to 4th January, 1964 on account of non-availability of postage stamps worth 1 nP.; and

(*b*) if so, the reasons for the shortage of these stamps ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (*a*) Inquiries made reveal that shortage of 1 nP. denomination stamps did occur during the period in question.

(*b*) Due to inadequate supplies from the Security Press and the local Treasury.

Disappearnce of Money from Insured Cover

330. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a sum of Rs. 19,000 was found missing from four insured covers sent from Pathankot to Allahabad in December, 1963 and waste papers were found therein instead of currency notes; and

(*b*) if so, the result of the enquiry ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (*a*) Pieces of paper were found from 4 letters insured for Rs. 19,000.

(*b*) It has not been established that the currency notes were enclosed in the letters.

Railway Track Between Delhi And Bombay

331. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government are doubling the railway track between Delhi and Bombay;

(*b*) if so, whether the bridges, like the one between Daud and Godhara and the other between Kotah and Bina, have already cracked, and whether payments regarding the same have been made by Government;

(*c*) whether these bridges will be reconstructed; and

(*d*) if not, the reasons therefor and the alternative measures that would be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (d) It is not clear from the question whether the Hon'ble Member has referred to bridges on the doubling work now in progress between Delhi and Bombay, or to the bridges on the sections already completed. At present only the doubling between Lakheri and Bayana is in progress. There are no cases of any cracks on bridges on this section where the doubling is in progress. However, on the Godhra-Nagda section, where doubling work was completed in 1962, some cracks have occurred in the pre-stressed concrete girders on some of the bridges, where these were provided. This matter is under investigation.

The Kotah-Bina section has not been doubled, and, in fact, this section is not part of the Delhi-Bombay route.

Fire In Wagon

332. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nine cows were burnt to death due to fire in one of the wagons of a goods train between Bhita and Dinapur Railway Stations on Eastern Railway on the 30th December, 1963;

(*b*) if so, the cause of fire; and

(*c*) the extent of damage caused thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) No. However, on 31-12-1963, 7 cows and 1 calf died when one cattle wagon loaded with 8 cows and 1 calf in Down Dumraon pilot goods train caught fire, while it was on run between Bhita and Neora stations.

(*b*) Due to oscillation of the train, a hurricane lantern hung inside the wagon carelessly by the cattle attendants, fell down on the straw bundles kept as fodder and ignited the straw.

(*c*) Public property damaged amounted to Rs. 1455/- approximately, including the value of cattle.

Cement Sleepers

333. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the progress made so far in the manufacture of Cement (concrete) Sleepers; and

(*b*) the areas in which these sleepers have been laid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) Global tenders were invited for indigenous manufacture and supply of concrete sleepers and on the basis of these, an order is being placed for manufacture and supply of 2 lakh numbers reinforced concrete sleepers.

These sleepers are intended to be laid on the Northern Railway after manufacture.

(*b*) In the past concrete sleepers, mostly manufactured departmentally by the Railways, were laid for trial in small lengths over various Railways.

दिल्ली में यमुना के ऊपर नावों का पुल

३३४. **श्री कछवाय :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली बार दिल्ली में यमुना के ऊपर नावों का पुल बनाने पर कितनी लागत आई थी;

(ख) इस पुल को गिराने, पुन: बनाने और मरम्मत आदि पर कितना आवर्त्तक वार्षिक व्यय होता है ;

(ग) क्या इस पुल का यमुना के पार दूसरी ओर रहने वाले निम्न आय वर्ग लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस के स्थान पर, एक पक्का स्थायी सड़क का पुल बनाने में कितना समय लगेगा?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३१६/६४]।**

सहकारी कैंटीनें

३३५. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलों और विशेषकर दक्षिण रेलवे की सभी वर्कशापों में कर्मचारी सहकारी कैंटीन खोलने का काम पूरा किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि १९६१ से गोल्डन राक वर्कशाप में कर्मचारी सहकारी कैंटीन के लिये कर्मचारियों से अंश एकत्रित करने के बावजूद सहकारी कैंटीन नहीं खोली गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस वर्कशाप को सहकारी कर्मचारी कैंटीनें खोलने के मामले में अन्य दुकानों के बराबर इस वर्कशाप को लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे की सभी वर्कशापों में कैंटीनों की व्यवस्था की गई है, परन्तु राज्य सरकारों द्वारा फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार यह अनिवार्य नहीं कि फैक्टरियों की कैंटीनें अंशपूंजी जुटाकर सहकारी आधार पर कर्मचारियों द्वारा चलाई जाएं ।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). अंश का मूल्य ५ रूपये के स्थान पर १ रुपये निश्चित करने का कर्मचारियों का सुझाव व्यवहार्य नहीं समझा गया, अतः यह फैसला किया गया कि दस सदस्यों वाली प्रबंधक समिति के द्वारा, जिन में पांच निर्वाचित हों और पांच रेलवे प्रशासन द्वारा नामांकित हों, कैंटीन को चलाने के लिये, एक विभागीय व्यवस्था तब तक चलती रहे जब तक सहकारी आधार पर कैंटीन को चलाने के लिये स्थिति अच्छी न हो जाए।

एयर इंडिया के किराये

३३६. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया ने हाल ही में यूरोपीय उड़ानों के लिये अपना किराया कम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). यरोपीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया के भाड़ों में हाल में कोई कमी नहीं हुई। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की बहुत सी बैठकें साल्ज़बर्ग (आस्ट्रेलिया) नासौ (बाहापास) और मौंट्रियल (कनाडा) में, एक ओर अमरीका तथा कनाडा के बीच के स्थानों तथा दूसरी ओर यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा एशिया के स्थानों के बीच १ अप्रैल, १९६४ से प्रभावी होने वाले पुनरीक्षित ट्रांस-अतलांतिक किराये अपनाने के लिये हुई है। डसके परिणाम स्वरूप, एक ओर अमरीका और कनाडा के स्थानों तथा दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान तथा लंका के स्थानों के बीच १ अप्रैल, १९६४ से किराया कम हो सकते हैं यदि सभी संबद्ध सरकारों ने इसे मंजूरी दे दी।

कांगड़ा घाटी का पुनर्मार्गरेखण

३३७. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की कांगड़ा घाटी रेलवे (नैरो गेज) सेक्शन के संबंध में, पोंग बांध के निर्माण के कारण इसके पुनर्मार्गरेखण के लिये परियोजना प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन पूर्ण कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक ये पूर्ण हो जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन मार्च, १९६४ तक पूर्ण होने की आशा है। प्रतिवेदन की विस्तृत जांच की आवश्यकता इस के पश्चात होगी।

पर्वतीय विकास सलाहकार बोर्ड

३३८. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय विकास सलाहकार बोर्ड की स्थापना के बारे में किन राज्यों ने अभी तक उत्तर नहीं भेजे ; और

(ख) कब तक उनके उत्तर आने की अपेक्षा की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). संबद्ध राज्यों से उत्तर आ चुके हैं और इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

बड़े पत्तनों का यंत्रीकरण

३३९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े पत्तनो के मंत्रीकरण का मामला विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). भारत के बड़े पत्तनों में फोर्क लिफ्टों, ट्रैक्टरों, चलती फिरती क्रेनों, जिटने मोटरों, आदि के रूप में कुछ मशीनीकृत माल उठाने धरने की सुविधाएं विद्यमान हैं। विभिन्न पत्तनों द्वारा हाल के वर्षों में इन का बड़ी भारी संख्या में अभिग्रहण किया गया है। इनको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा और जहां कहीं आवश्यकता होगी उपकरण को आधुनिक ढंग का बनाया जाएगा। विभिन्न पत्तनों में आधुनिकृत भारी माल धरने रखने का उपकरण लगाने की संभावनाओं पर भी समय समय पर विचार किया जाता है।

कोयला तथा लोहा अयस्क भारी मात्रा में धरने रखने की कुछ मशीनीकृत सुविधाएं कलकत्ता पत्तन में विद्यमान हैं। खाद्यान्न को मशीनों द्वारा लादने तथा उतारने के लिये किड्डरपोर गोदियों में एक सिलो लगाया जा रहा है। नवीन हाल्दिया गोदी में, बहुत बड़ी मात्रा में कोयला तथा अयस्क लादने उतारने के लिये पूर्णतः मशीनीकृत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है।

बम्बई में भारी मात्रा में खुश्क माल प्रमुख रूप से खाद्यान्न होता है, जो वैकुएटरों के द्वारा जहाजों से उतारा जाता है। सरकार का ५०,००० टन क्षमता का एक अनाज सिलो बम्बई पत्तन पर बनाने का विचार है । गोदी विस्तार योजना में सम्मिलित अलैग्जैंडर गोदी के पूर्वी कक्ष के प्रस्तावित विस्तार में दो नवीन बर्थों पर खाद्यान्न की मशीनों द्वारा उतारने के लिये उपकरण लगाया जाएगा। स्वतः माप करने और बोरों में भरने की व्यवस्था करने तथा अनाज सिलो पर मशीनों द्वारा वैगन भरने की व्यवस्था करने का भी विचार है।

मद्रास में, अर्ध-मशीनीकृत धरने रखने का उपकरण, अर्थात ट्रांसपोर्टर पुल क्रेन, बिजली का व्हार्फ क्रेन, लोकों, वैगन आदि की व्यवस्था लोहा अयस्क को धरने रखने के लिये की गई है। जहाजों से कोयला उतारने के लिये कोयला बर्थ पर ग्रैब क्रेनें लगाई गई हैं। मद्रास पत्तन में लगभग २,००० टन प्रति घंटा लादने उतारने के लिये सक्षम एक पूर्णतः मशीनीकृत अयस्क लादने का संयंत्र लगाया जाएगा।

विशाखापटनम में, उत्तरी कक्ष में दो गहरे ड्राफ्ट बर्थ-बनाये जा रहे हैं, जिन में प्रति घंटा लगभग २६०० टन लादने उतारने के लिये सक्षम एक मशीनीकृत अयस्क लदान संयंत्र लगाया जाएगा।

मोरमुगाओ पत्तन पर, इस समय एक गैर-सरकारी मशीनीकृत अयस्क लदान संयंत्र लगा है। इस की क्षमता सीमित है। इस पत्तन पर बड़े पैमाने पर मशीनीकृत अयस्क लदान का विकास करने की संभाव्यता का विचार किया जा रहा है।

उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था

३४०. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था के निदेशक, सहायक निदेशक और प्रवर वैज्ञानिक अधिकारियों के पद अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रखे गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संस्था युनेस्को से प्राप्त धन से स्थापित की गई थी ; और

(ग) क्या सस्था में उपरोक्त पदों को अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित करने के मामले में निर्णय युनेस्को के परामर्श से किया गया था ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि की सहायता से स्थापित की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

३४१. श्री हेम राज : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, गत छः महीनों में राज्य वार कितने उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये ;

(ख) क्या यह सच है कि उन में विविध वस्तुओं के लिये जो दर ली जाती है वह बाजार भाव से अधिक होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी०-२३२०/६४]**।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bakhtiarpur-Rajgir Railway Line

342. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the decision, if any, taken on the preposal to extend the Bakhtiarpur-Rajgir line up to Varasliganj/Gaya?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): There is no proposal at present, under consideration for extensiou of Bakhtiarpur-Rajgir line upto Varasliganj/Gaya, nor is it included in Railways' programme for construction of new lines during the Third Plan as approved by the Planning Commission.

जापानी विमान दल

३४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ सदस्यों वाला जापानी विमान दल असैनिक कार्यों के लिये भारत की विमानों सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये इस वर्ष जनवरी में भारत आया ;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में उन की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन उपपत्तियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) चर्चा के बीच जापानी दल ने भारत में असैनिक उपयोग के लिये विमान संबंधी आवश्यकताओं पर सूचना मांगी और जापान में बनने वाले हालीकाप्टर समेत विभिन्न प्रकार के विमानों के सामान्य विवरण दिये। उन के द्वारा कोई उपपत्तियां बताने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के सामान की चोरी

३४४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रेलवे मंत्रालय के केन्द्रीय ब्यूरो ने टूंडला-हाथरस सैक्शनों पर बड़े पैमाने पर रेलवे सामान की चोरी के लिये उत्तरदायी दल के छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) विश्वस्त सूचना के आधार पर ट्रक संख्या यू० पी० ए० ६१४१ का पीछा केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा २३/२४ नवम्बर, १९६३ की रात्रि को आगरा से जलेसर रोड स्टेशन तक, जो उत्तर रेलवे के टूंडला-हाथरस सैक्शन की मुख्य लाइन पर स्थित है, किया गया। ट्रक माल गोदाम के पास रोका गया जहां ढाले गये लोहे के स्लीपरों के भारी बंडल रखे थे। अपराधी बड़ी संख्या में थे और उन्होंने स्लीपरों को लादना आरम्भ कर दिया। जब ट्रक का कुछ भाग लद गया, रेलवे सुरक्षा बल रक्षकों; जो जलेसर रोड स्टेशन पर ड्यूटी पर थे, तथा केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, रेलवे मंत्रालय ने असैनिक पुलिस की सहायता

से भरे हुए ट्रक को तथा छः अपराधियों को पकड़ लिया। शेष अपराधी भाग गये। सरकारी रेलवे पुलिस अलीगढ़ ने धारा ३७९ भा० दं० सं० के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर दिया है, जिसकी अभी जांच हो रही है।

भारत के रास्ते नेपाल-पाकिस्तान व्यापार मार्ग

३४५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार भारत में राधिकापुर के रास्ते नेपाल-पाकिस्तान व्यापार चलाने का मार्ग बनाने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार तथा यातायात सन्धि १९६० के अन्तर्गत, नेपाल ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि पाकिस्तान के साथ उनके व्यापार के लिये राधिकापुर में यातायात सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार ने ये सुविधायें देना मान लिया है।

सुपारी

३४६. **श्री केप्पन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सुपारी समिति ने सुपारी की फंगस बीमारी का सर्वेक्षण करने की योजना की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) क्या एक अफसर को अन्दमान से अच्छे बीज इकट्ठे करने के लिये वहां भेजने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): जी हां।

मत्स्यपालन का विकास

३४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में मत्स्यपालन के विकास के लिये राज्य सरकारों को राज्यवार केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई ; और

(ख) १९६४-६५ में कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ऋणों और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता की राशि, जिसके लिये राज्य सरकार १९६३-६४ में मत्स्यपालन के विकास के लिये पात्र हैं, मार्च १९६४ में, उनके द्वारा पहले नौ महीनों में किये गये वास्तविक व्यय तथा शेष तीन महीनों में प्रत्याशित व्यय के आधार पर दिये जाएंगे। तकनीक वर्ष १९६३-६४ की बजट व्यवस्था के आधार पर केन्द्रीय सहायता का राज्यवार अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २३२१/६४]**

(ख) १९६४-६५ में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की कुल राशि का अनुमान ११० लाख रुपये है (६० लाख रुपये ऋणों में और अनुदान में ५० लाख रुपये)। ये आंकड़े योजना आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उन के योजना परिव्यय के आधार पर आंके गये हैं। वर्ष १९६४-६५ के लिये राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप से व्यवस्थित परिव्यय अभी मालूम नहीं हुए हैं।

पंजाब म टेलीफोन

३४८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में नवीन टैलीफोनों की बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी, १९६४ तक कितनी अर्जियां लंबित थीं ; और

(ग) इस काम को शीघ्रतापूर्वक करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब डाक व तार मंडल के ऐक्सचेंजों से टेलीफोनों की लंबित अर्जियों की संख्या ९६९३ है।

(ग) ऐक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि लंबित मांगें अधिक से अधिक पूरी की जा सकें।

मैसूर में सहकारी चीनी फैक्टरियां

३४९. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में मैसूर राज्य में कितनी नवीन सहकारी चीनी फैक्टरियों को लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या अन्य सहकारी चीनी फैक्टरियों को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी हां। इस समय बहुत सी अर्जियां विचाराधीन हैं।

(ग) इस मामले में आगामी कुछ सप्ताहों में अन्तिम निर्णय किये जाने के पश्चात् मालूम होगा।

उर्वरकों का आयात

३५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के भेजे गये क्रयादेशों में से अब तक उर्वरक का कितना आयात हुआ है ;

(ख) संतुलन आवंटन में से उर्वरकों के आयात के लिए किन देशों को अग्रतर क्रयादेश दिये गये हैं और कितने माल के ;

(ग) १९६३ में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ; और

(घ) १९६४ में ट्रैक्टरों के आयात के लिये कितना नियतन किया गया है और आयात करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) १९६४-६५ में उर्वरकों के आयात के लिए आवंटित ३० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में ये क्रयादेश दिये गये हैं :—

स्रोत	विवरण	मात्रा टनों में	मूल्य रुपयों में
			करोड़ रु०
१. जापान .	यूरिया	५०,०००	१·९५
२. पूर्वी जर्मनी	अमोनिया सल्फेट	११,०००	०·२५
३. अमरीका	अमोनिया सन्फेट	१,९७,६०५	
	अमोनिया फास्फेट	४०,०००	९·०७
	नाइट्रो फाल्फेट	३०,०००	
४. इटली .	अमोनिया सल्फेट	२५,०००	०·५३
५. इंगलिस्तान	अमोनिया सल्फेट	२०,०००	०·४२
		योग .	१२·२२

मार्च १९६४ तक भारत में उर्वरक आना प्रारम्भ होने की आशा है। अग्रेतर क्रय के बारे में बातचीत की जा रही है।

(ग) ३७९० ट्रैक्टर के लिये दिए गये लाइसेंस में से अभी आयात हो रहा है। नवम्बर १९६३ तक १५०० ट्रैक्टर आये हैं।

(घ) १९६४ में ट्रैक्टर के आयात के लिये निम्न नियतन किया गया है :—

स्रोत	ट्रैक्टर संख्या	मूल्य रुपय में
		करोड़ रुपये
रूस	१४०३	१·००
पोलैंड	१००० (एस० के डी० पैक्स)	०·३०

इन ट्रैक्टरो के आयात लाइसेंस बिये जा रहे हैं।

तब से १९६४ में पौलैंड से १००० और एस० के० डी० पैक्स का आयात करने का निर्णय किया जा चुका है।

कपास और तिलहनों की सघन खेती

३५१. { डा० महादेव प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कपास, तिलहन और खाद्यान्न की सघन खेती के प्रस्तावों पर राज्यों के अधिकारियों की बैठकों में चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आएंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) चावल, गेहूं तथा तिलहन की सघन खेती के लिये अन्तिम रूप से लिए जाने वाले जिलों की सूचना अभी राज्यों की सरकारों ने नहीं दी। उत्तर प्रदेश में कपास की सघन खेती आरम्भ करने का विचार नहीं है।

अवशिष्ट राशि का भुगतान

३५२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, नई दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता के तार घरों के दिहाड़ी वाले विभागातिरिक्त टैलीग्राफिस्टों की अवशिष्ट राशियां १९६२ के मंत्रालय के पत्र के अनुसार दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) भुगतान शीघ्रता से हो, इसके लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास राज्य में चीनी मिलें

३५३. **श्री द्वारिका दास मंत्री :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने ५० टन क्षमता की छोटी चीनी फैक्टरियां अपने राज्य में स्थापित करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

३५५. **श्री सं० च० पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के हुबली डिवीजन में बागलकोट तथा बीजापुर के रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों की व्यवस्था है; और

(ख) १९६४-६५ में कितने कर्मचारियों को क्वार्टर देने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस समय बीजापुर में ५७ तथा बागलकोट में ४९ क्वार्टर हैं।

(ख) १९६४-६५ में बागलकोट में दो तथा बीजापुर में छः क्वार्टर बनाने का विचार है।

इम्फाल तथा लीलावाड़ी में हवाई अड्डे

३५६. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या परिवहन मंत्री १० दिसम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१९ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि फोक्कर फ्रेंडशिप सेवाओं तथा एफ–१२ ओप्रेशनों के लिए इम्फाल तथा लीलावाड़ी के हवाई अड्डे कब तैयार हो जाएंगे ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : इम्फाल (टुलीहाल) तथा नीलावाड़ी (उत्तर लखीमपुर) हवाई अड्डों में धावनपथों को लम्बा तथा मजबूत करने के काम की मंजूरी दी जा चुकी है ताकि फोक्कर फ्रेंडशिप विमान की उड़ान तथा उतार के लिए वे उपयुक्त हो सकें। ये काम क्रमशः १९६५ के अन्त तक तथा १९६६ के मध्य तक पूरे हो जाने की आशा है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

शिलांग में कर्फ्यू लगाया जाना और सेना को बुलाया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे शिलांग में कर्फ्यू तथा सेना के बुलाये जाने के बारे में ३ स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन में से पहला श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का है जिस के लिए मैं अनुमति नहीं दे सकता चूंकि उन्होंने नहीं बताया कि सरकार किस प्रकार अपने कार्य में सफल रही है। दूसरा श्री स्वैल का है। वह बतायें कि इस में केन्द्रीय सरकार किस प्रकार अन्तर्ग्रस्त है।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त जिले) : यह इस प्रकार है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये सेना बुलायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बतायें कि सेना को किन परिस्थितियों में बुलाया गया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सेना को बुलाया जाना संसद् के क्षेत्र की बात है। इस विशेष मामले में जो घटनायें सेनायें बुला जाने से पूर्व हुईं वह भी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र की हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : पुलिस चूंकि वहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही इसलिये सेना को बुलाया गया। यह एक गम्भीर विषय है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : वहां पर झगड़ा ७ जनवरी को सुरक्षा बल द्वारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आरम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप शिलांग में घटना हुई। इसलिए, केन्द्रीय सरकार इसके लिए उत्तरदायी है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : वहां पर सेना दण्डाधीश के कहने पर असैनिक प्रशासन की सहायतार्थ भेजी गयी। मेरे पास इस से अधिक जानकारी इस समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि दण्डाधीश द्वारा अनुरोध किया गया था तो केन्द्रीय सरकार को वह सहायता देनी ही थी। इसलिए, इस में केन्द्रीय सरकार की असफलता का प्रश्न नहीं आता। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, वह जानकारी प्राप्त करेंगे और तब तक मैं इसे लम्बित रखूंगा। जानकारी उपलब्ध होने पर इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा। क्या यह कल सुबह तक उपलब्ध हो जायगी।

श्री नन्दा : जी हां।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री यह मालूम करें कि वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, जैसे सीमा सुरक्षा बल में मुठभेड़ जिसके परिणामस्वरूप एक सेना अधिकारी की मृत्यु हुई, और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय लोगों में, डाकी में, मुठभेड़, आदि . . . . . ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बातें माननीय मंत्री को लिख सकते हैं।

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : What is the position regarding our Calling Attention Notice?

Mr. Speaker : Calling Attention Notices shall also remain till we decide about Adjournment Motions. I may admit the Adjournment Motions in the shape of Calling Attention Notices. If it is admitted as Adjournment Motion, the Calling Attention Notice will also be there.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, १९६४

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं (१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२ में प्रकाशित भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २३०४/६४]

विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले विवरण

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं (२) विभिन्न अधिवेशनों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने बताया गया है मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा

प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ छठा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३०५/६४]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ पांचवां सत्र, १९६३ (तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३०६/६४]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३०७/६४]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ११ तीसरा सत्र, १९६२–६३ (तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३०७/६४]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १३ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३०९/६४]

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १६ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३१०/६४]

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २२ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २३११/६४]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं (३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४४ में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(दो) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४५ में प्रकाशित चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६३ ।

(तीन) दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५२ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण दूसरा संशोधन आदेश, १९५३ ।

(चार) दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५३ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (लाने ले जाने पर रोक) तीसरा संशोधन आदेश, १९६३ ।

(पांच) दिनांक ३ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१ में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६४ ।

(छै) दिनांक ७ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४ में प्रकाशित चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६४।

(सात) दिनांक ७ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५ में प्रकाशित मद्रास चावल समाहार (शुल्क) आदेश, १९६४।

(आठ) दिनांक ८ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६ में प्रकाशित चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६४।

(नौ) दिनांक ९ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७।

(दस) दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९७ जिसमें दिनांक १९ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७३ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६३ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(ग्यारह) दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०० में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल समाहार (शुल्क) संशोधन आदेश, १९६४।

(बारह) दिनांक २ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७ में प्रकाशित भारतीय मक्का (मांड बनाने के लिये अस्थायी प्रयोग) आदेश, १९६४।

(तेरह) दिनांक २३ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८ में प्रकाशित चावल (मद्रास) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६४।

(चौदह) दिनांक ३० जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७० में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६४।

(पन्द्रह) दिनांक ३० जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६४।

(सोलह) दिनांक ३ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६४।

(सत्रह) दिनांक ३ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २३१२/६४]

जूने के पत्थर तथा डोलोमाइट खनन उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड तथा लौह अयस्क खनन उद्योग क सम्बन्ध में कन्द्रीय मजूरी बोर्ड के बारे में संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं (४) निम्नलिखित संकल्पों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) दिनांक ५ फरवरी, १९६४ का संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०-२ (३७)/६३ जिसमें चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट खनन उद्योगों के संबंध में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने की घोषणा की गई है ;

(दो) दिनांक ५ फरवरी, १९६४ का संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-२ (३६)/६३ जिसमें लौह अयस्क खनन उद्योग के संबंध में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने की घोषणा की गई है।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २२५७/६४)

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६३-६४

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1963—64

वित्त मंत्री (श्री ति० न० कृष्णमाचारी) मैं वर्ष १९६३–६४ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक--उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT DISCHARGING THF FUNCTIONS OF THE PRESIDENT.

अध्यक्ष महोदय : अब १३ फरवरी, १९६४ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी ; अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति का कार्य निर्वाहन करते हुए उप-राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये उनके अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १० फरवरी, १९६४ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।"

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (वारपेटा) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

इस अभिभाषण में सरकार की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सफलताओं की प्रेरणाजनक तस्वीर खींची गयी है। आन्तरिक मामलों में सरकार के जनतांत्रिक एवं समाजवादी उद्देश्य और विदेशी मामलों में तटस्थता की नीति का समर्थन सारा देश करता है।

परन्तु हमें इस प्रगति के कारण आत्मतुष्टि की भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। मैं उप-राष्ट्रपति के इस कथन का स्वागत करती हूं कि हमें अपने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये अपने प्रतिरक्षा साधनों को और सुदृढ़ बनाना है। हमें बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना है और प्रशासन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है। हमें यह भी देखना है कि सभी राज्य साथ साथ विकास की ओर अग्रसर हों।

आसाम राज्य की भी बहुत सी समस्यायें हैं। वह समस्यायें विभाजन और पाकिस्तान से अवैध प्रवेश और वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने के कारण उन का इस देश में आना, इन सब कारणों से और भी भीषण हुई हैं। चीन के आक्रमण से भी आसाम की आर्थिक स्थिति आदि की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आसाम की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

हम ने देखा है कि किस प्रकार चीनी आक्रमण के पश्चात् रेलवे लाइनों पर ध्वंसात्मक कार्य किये गये, हमारे पुलों को उड़ाने के प्रयास किये गये। इसलिये हमें अपनी गुप्तचर सेवा की कुशलता की ओर विशेष ध्यान देना है।

आसाम की सीमा पार कर के बर्मा से कोई भी आ जा सकता है। बर्मा में विद्रोही साम्यवादियों का केन्द्र है इसलिये उस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अवैध प्रवेश करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिये पहले आसाम के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया और बाद में उसकी जगह एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। मैं समझती हूं कि विशेष अधिकारी की जगह बेहतर होगा यदि इस संबंध में राज्य सरकार को अधिक शक्तियां दे दी जायें। यदि घुसपैठ करने वालों की समस्या का तुरन्त समाधान न किया गया तो कुछ वर्षों में एक नयी समस्या आसाम में खड़ी हो जायेगी।

गृह-कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य प्राईमरी शिक्षा के बारे में पूर्वी प्रदेश परिषद् के समक्ष दिया वह भ्रमपूर्ण है।

पहले मनीपुर और त्रिपुरा को आसाम से अलग किया गया। फिर नागालेंड बनाया गया और अब पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी उपबन्धों पर विचार हो रहा है। मैं समझती हूं कि यह संसदीय लोकतंत्र के कायदे के अनुसार नहीं होगा। इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों को निर्वाचित शक्तियां दी गयी हैं जो बात अनुचित है इस से देश में वियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

फ़िजो के विरुद्ध हालांकि इतने बड़े अभियोग हैं फिर भी उसे नागालेंड में शांति स्थापित करने के लिये बुलाना एक दुर्बल नीति है। इस का अर्थ यह है कि उस के बिना वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। फिजो के साथ समझौता करने की चेष्टा का गलत मतलब लिया जा रहा है। और यह कार्यवाही एक ऐसे समय में की जा रही है जब कि विद्रोही नागा पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के जरिये चीन से भी साज बाज कर रहे हैं। इस विषय में न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

पाकिस्तान से ५०,००० से अधिक अल्पसंख्यक आसाम में आ गये हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे लिये यह कितनी भीषण समस्या बन गयी है इसके बावजूद भी साम्यवादी पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों की चर्चा कर रहे हैं। साम्यवादी पहले भी दो बार हमारे साथ चालबाजी कर चुके हैं परन्तु हमारी दुर्बल नीति के कारण वह बचे रहे। आज वह पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों के साथ संहानुभूति कर के ५ करोड़ मुसलमानों के साथ मित्रता गांठना चाहते हैं। इस से हमें खबरदार रहना है। साम्यवादियों द्वारा ऐसी आवाज उठाना इस लिये और भी खतरनाक है कि इस समय सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले पर चर्चा हो रही है। साम्यवादी एक भी मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकते जब कि भारत में मां-बाप के सामने बच्चों को कत्ल किया गया हो या लड़कियों के साथ व्यभिचार किया गया हो।

इन शब्दों के साथ में उप-राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट करती हूं।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य बराबर गिर रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गयी है कि लोगों के लिये जीवन-निर्वाह करना कठिन हो गया है। हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, अक्षमता और अकुशलता का बोलबाला है।

हमारी विदेश नीति बुरी तरह असफल रही है। यहां तक कि संसार में आज हमारा कोई मित्र नहीं रहा। सुरक्षा परिषद् में काश्मीर पर बहस के समय यह साबित हो गया कि रूस का रुख हमारे तईं पहले जैसा नहीं रहा है। इस क्षीण स्थिति के लिये न तो कोई दैवी शक्ति उत्तरदायी है और स्वयं इस देश के लोग यह बात चीनी आक्रमण के समय सिद्ध हो गयी थी। यह मेरा ही नहीं वरन् देश के बड़े बड़े लोगों का मत भी है कि हमारे नेता इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं। जिस देश में नैतिकता और कानून में सामंजस्य न रहे उस देश में सिवाये अन्धेरगर्दी के कुछ नहीं पनप सकता। जब तक इस अन्धेरगर्दी का अन्त नहीं किया जाता तब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक उत्थान होना असम्भव है। इस लिये सभी सच्चे नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वह कानून और नैतिकता को अलग न होने दें।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : में उप-राष्ट्रपति के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हम ने समाजवादी व्यवस्था की ओर प्रगति की है। हमारे देश में केवल दो प्रकार के लोगों की समृद्धि हुई है एक तो सरकार के उच्च अधिकारी और दूसरे लाईसेंसधारी। इन दो वर्गों के लोगों को तो ऋण दिये जा रहे हैं। वह बंगले बना रहे हैं। परन्तु कच्ची बस्ती में रहने वालों को उन की झोंपड़ियों से निकाला जा रहा है और बदले में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा।

उप-राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया कि कृषि उत्पादन मे कमी का कारण मौसम की खराबी है परन्तु इस का वास्तविक कारण सरकार की भूमि-सुधार संबंधी त्रुटिपूर्ण नीति है। हम रूस की नीति का अनुसरण कर रहे हैं जब कि स्वयं रूस में भूमि संबंधी प्रयोग असफल रहे हैं। आज किसान भूमि पर अधिक मेहनत नहीं करता चूंकि उसे भय रहता है कि किसी समय भी उस की भूमि छीन ली जा सकती है। यदि किसान को आश्वासन दिया जाय कि उस की भूमि नहीं ली जायगी और वह जो कुछ पैदा करेगा उस का लाभ उसे ही मिलेगा, तो वह अधिक उत्पादन करेगा।

गुड़ और चीनी की कमी के कारण सरकार की वितरण व्यवस्था का त्रुटिपूर्ण होना है। यह कोई दैवी विपत्ति नहीं है। राजस्थान और गुजरात के साथ विशेषकर पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जिस के परिणामस्वरूप वहां पर चोरबाजारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

भ्रष्टाचार से जो खतरा पैदा हुआ है वह चीनी आक्रमण के खतरे से भी बड़ा है। इस भ्रष्टाचार के लिये कांग्रेस के लोग उत्तरदायी हैं। इसीलिये, कल तक जिन कांग्रेस-जनों का सम्मान किया जाता था आज उन को बुरी नजर से देखा जाता है। आज रिश्वतखोरी बढ़ रही है। इसी लिये सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया है। परन्तु इस आयोग के पास मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की शक्ति नहीं है वरना कई एक ऐसे मामले हमारे सामने आते।

सरकार को चुनाव-पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए। बड़े बड़े लोग कोटे और लाईसेंस दे कर संगठन के लिये निधियां प्राप्त करते हैं और यही सब बुराईयों की जड़ है। इस के साथ

साथ, मंत्रियों को चुनाव संबंधी प्रचार की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह अपनी स्थिति का लाभ उठा कर मत प्राप्त करते हैं। अपने चुनाव से ६ मास पूर्व उन्हें प्रशासन से अलग हो जाना चाहिए। एक दल के कार्यक्रम संबंधी प्रचार स्वयं चुनाव आयोग को करना चाहिए ताकि चुनाव संबंधी व्यय कम हो।

चुनाव सम्बन्धी नियमों में सुधार की दृष्टि से एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

सरकार का पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में चिन्तित होना सन्तोषजनक बात है। राजनीतिक उद्देश्यों से बच्चों और स्त्रियों को कतल करना एक खेदजनक बात है।

श्री कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश सरकार और पाकिस्तान की आलोचना करके सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। परन्तु हमें नहीं भूलना है कि चीन के आक्रमण के लिये वही उत्तरदायी थे। श्री मेनन के शासन से अलग हो जाने का हमें खेद नहीं होना चाहिए चूंकि उन से भी कहीं अधिक कुशल व्यक्ति, श्री चागला, की सेवायें सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों में अच्छी प्रगति हुई है। इन उपक्रमों के लेखे जोखे की संसद द्वारा जांच की जानी चाहिये। इस उद्देश्य से गत सत्र में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। परन्तु अभी तक उसकी स्थापना नहीं की गई है। संसद का मुख्य कृत्य सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना है। इन उपक्रमों पर भारी व्यय किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समिति की तत्काल स्थापना की जानी चाहिये।

हमें ऐसे व्यक्तियों की जो चीनी भाषा जानते हों अधिक संख्या में आवश्यकता है। यहां आने वाले कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि यहां चीनी भाषा के अध्ययन के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह कहा जाता है कि हमारे संसाधन सीमित हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें किसी और दिशा में कुछ कमी करके इस ओर अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये। हमें अपनी राजनयिक सेवाओं, विश्वविद्यालयों, आदि के लिये चीनी भाषा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ौसी देशों की भाषाओं के अध्ययन की सुविधायें देश वासियों को उपलब्ध करायें। विशेषकर आपातकाल मे विदेशी भाषाओं में निपुण व्यक्तियों की सेवायें बड़ी मुल्यवान होती हैं। अतः सरकार को इस दिशा में अधिक प्रयत्न करने चाहियें।

सभा में यह आवाज उठाई गई है कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि इस से लोगों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबन्ध लग जाते हैं। इसे समाप्त करने की सब से अधिक मांग साम्यवादियों द्वारा की जा रही है। हमें तीन बातों को ध्यान में रख कर इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिये। पहला यह है कि क्या इस समय आपातकाल को समाप्त करना उचित है ? दूसरे, क्या ऐसा करना व्यवहार्य है ? तीसरे, क्या ऐसा करन देश की सुरक्षा की दृष्टि है अच्छा होगा ? हमारी सीमा पर एक ऐसा शत्रु बैठा है जो कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। आजकल का समय ऐसा है जब कि जासूस सभी देशों में शत्रु के जासूस तथा अन्य देश विरोधी तत्व से भरे हुए हैं। अतः ऐसी दशा में आपातकाल को समाप्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

श्री कु० शिवप्रधासन (पांडिचेरी): मुझे प्रसन्नता है कि मुझे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । मैं इसके लिये भारत सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने पांडिचेरी की ओर विशेष ध्यान दिया है । १९५४ से १९६२ तक भारत-सरकार तत्काल विकास कार्य करने में असमर्थ रही क्योंकि पांडिचेरी का विधिवत् हस्तांतरण इस में बाधक था । परन्तु इसके बावजूद भी वहां पर बहुत कुछ विकास कार्य किया गया । शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है । वहां पर मेडिकल कालेज, डिग्री कालेज तथा पोलीटैकनिक की स्थापना की गई है । स्कूल भी काफी संख्या में खोले जा रहे हैं। एक चीनी कारखाना भी लगाया गया है । पुराने पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण किया गया है ।

पांडिचेरी की नागरीय जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय वाणिज्य है । भारत में विलय के पश्चात् वहां पर भी भारत के अन्य भागों की तरह आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इसका उन वर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । इसका एक मात्र उपाय यह है कि उन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाये। भारतीय उर्वरक निगम की ओर से इंजीनियरों का एक दल वहां पर एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिये भेजा गया था । परन्तु अब यह सुना गया है कि उसके पांडिचेरी या किसी अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यह एक नवोदित राज्य के लिये निराशाजनक बात है। गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पेपर मिल की स्थापना के लिये आवश्यक सुविधा देने के लिए भी कई बार आवेदन किये गये हैं परन्तु पता नहीं इस मामले में देर क्यों की जा रही है ।

चूंकि यह मेरा प्रथम भाषण है अतः मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही अपने विचार सीमित रखूंगा । अन्त में मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि पांडिचेरी में छोटे तथा बड़े उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं को, जहां तक सम्भव हो सके, स्वीकृति प्रदान की जायें।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I rise to support the Motion of Thanks on the Vice-President's Address. I do agree with Acharya Kripalani that corruption and other social evils are ampant in India. But I do not agree with this observation that demoralisation got impetus from public workers. I can say with confidence that the oppositiion parties have not contributed less to the social evils. The opposition gives shelter to a man who is ousted from society or a political party on account of corruption.

If we are bent upon eradicating corruption all of us should take a united stand to fight out corruption and formulate a code of conduct for the society as a whole. This is the only effective way to solve this problem.

It is true that progress has been achieved under the five year plan, but it is a matter of concern that the prices have gone up tremendously. The prices of wheat, for instance, have gone up by Rs. 20/- per maund. This kind of porfiteering should be put a stop to. Government should take stringent steps to end this kind of profiteering.

Controls have aggravated the situation, otherwise the shortage would not have been so acute. People are starving. In my village, a mob looted the bazar in broad day light. They took away only foodgrains. It is, therefore, a warning to the Government that they should view the situation seriously. Our distribution system is also faulty. Government supplies wheat to flour mills at Rs. 14/- per maund. It is to be sold at Rs. 16/- per maund, after turning it into flour. But the mills produce Rawa and Maida from that wheat and sell it at

[Shri M.L. Dwivedi]

Rs. 21/-. This kind of blackmarketing is going on. I urge that Government should either distribute it direct to the public or put a stop to this kind of blackmarketing.

So far as Kashmir is concerned, our attitude has been a defensive one. We should put our stand clearly before the world. Pakistan is an aggressor. The Pakistan-occupied Kashmir is legally a part of India. Unless this aggression is vacated, we should not adopt a defensive attitude. In the case of china, we should do enough publicity to counteract the Chinese propaganda. We should send teams to foreign countries to present our case before them in a just manner.

The working of community development Blocks has not been satisfactory. The work in every block has been entrusted to the Block Committees. But real development that has taken place there, is that beautiful bunglows have been constructed for the B. D. O. & his staff. Conditions of the villages have not been improved. In this connection I may cite here a very interesting example. A Commissioner visited a Block where he had to inaugurate a poultry breeding centre. The Commissioner visited three such centres there and to his surprise he saw the same fowl in all three of them. In fact he was held up for some time and offered tea while he was on his way from one to the other centre and in the meantime all the fowl of one centre were taken to the next one. The public should not be befooled in this manner. If we are serious about development we should see that the money is being spent judiciously. More money is being spent on the services. What is the position today? If a lakh of rupees are sanctioned for a project Rs. 50,000 go into the pockets of the concerned authorities, the contractor also takes about Rs. 10,000 and only 40,000 are spent on the project itself. Public money is being wasted like this. I hope that the Ministry will do some good work and utilise the grants judicioulsy in the coming year.

With these words I thank the Vice-President for delivering this Address.

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर): उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण में खेलों सम्बन्धी नीति को कोई उल्लेख नहीं है । अत: मैं खेलों के विषय पर ही बोलूंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair.]

१९६४ का वर्ष ओलम्पिक वर्ष है । देश के खिलाड़ियों का ध्यान आगामी अक्तूबर में टोकियो भेजे जाने वाले भारतीय दल पर केन्द्रित है । यदि सरकार चाहती है कि भारत कोई स्वर्ण पदक जीते तो उसे खिलाड़ियों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिये । अभी ८ महीने शेष हैं जिनमें हम अपने खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण दे सकते हैं । मैं राज कुमारी अमृत-कौर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने खेलों को बहुत प्रोत्साहन दिया । उनकी मृत्यु से हमें बड़ा धक्का पहुंचा है ।

सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् की स्थापना की है परन्तु यह बहुत अधिक सहयोग नहीं दे पाई है ।

सरकार की खेल कूद संबंधी नीति में कई कमियां हैं । जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में खेल कूद के लिये मैदानों का अभाव है । इन संस्थाओं में अच्छे अच्छे खिलाड़ी विद्यमान हैं जिन्हें खेल-कूद की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय फैडरेशन को अपने खिलाड़ियों से उचित स्तर का खेल नहीं मिल पा रहा है । फैडरेशनों को अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त रुचि लेनी चाहिए जिस से वे खेल-कूदों में उचित स्थान प्राप्त कर सकें । खेल कूद परिषद् तथा अन्य खेल-कूद संस्थाओं में राज्यों के शिक्षा विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । एक अखिल भारतीय खेल-कूद सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए और उस में खेल-कूद संबर्द्धन के लिए नीति के तौर पर सार्वजनिक संस्थाओं के सभी निदेशकों को आमंत्रित किया जाये। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् को जो खेल कूदों के संवर्द्धन के मामलों में सरकार की सलाहकार संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, इस सम्मेलन को प्रायोजित करना चाहिए। खिलाड़ियों के लिये हमें सेना और पुलिस पर निर्भर न रह कर अन्य देशों की भांति खिलाड़ी स्कूलों और कालेजों से चुनने चाहिएं ।

खेल-कूद के मैदान, उपकरण तथा निधि संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने के सभी शिक्षा संस्थाओं में नियमित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक संस्था में खेलकूद की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव मुख्य रूप से इन्हीं संस्थाओं से किया जाना चाहिए । राज्यों के शिक्षा विभागों में खेल-कूद विभाग पूर्ण रूप से एक उपनिदेशक के प्रभार में होना चाहिये । । प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त अध्यापक चुने जाने चाहिएं। शिक्षा संस्थाओं में खेल-कूद पर होने वाले व्यय का ६० प्रतिशत भाग तक सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए । पटियाला के राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बन्दूक चलाना और 'गोल्फ' भी शामिल किये जाने चाहिएं ।

खेल-कूद का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमारे खिलाड़ियों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना आवश्यक है । उन्हें विदेशी मुद्रा और पर्याप्त धन उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो अवसर न मिलने के कारण प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राज सहायता तथा अन्य सभी संभव सहायता दी जाय जिस से वे देश के लिये एक योग्य खिलाड़ी सिद्ध हो सकें । यदि विद्या संस्थाओं में बंदूक चलाने का अभ्यास कराया जाये तो हमें निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं के लिए योग्य निशानेबाज मिल सकते हैं।

मुझ यह सूचित करते हुये हर्ष होता है कि राजस्थान में खिलाड़ियों को राज्य सहायता देता है इसलिये वहां के खिलाड़ियों का नाम अच्छा है । मुझ आशा है मेरे अन्य मित्र भी अपने राज्यों में जाकर खिलाड़ियों को राज सहायता दिलाने के प्रयत्न करेंगे ।

खेल के मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण के लिये सरकार को "रैफल" डालकर धन की व्यवस्था करनी चाहिए । इस प्रकार सारे देश में खेल स्टेडियम बनाये जा सकते हैं जहां खिलाड़ियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है और भारत के खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों में अपना उपयुक्त स्थान बना लेंगे । स्टेडियमों की कमी दूर करने के लिये इन में प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे खिलाड़ी रात में भी खेल कूद कर सकें। सरकार को इस कार्यक्रम को अपनी योजनाओं में शामिल करने के संबंध में विचार करनाचाहिए ।

श्री चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समस्त क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास हुआ है परन्तु गांव अभी तक उपेक्षित ही पड़े हुये हैं वहां किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो पाई है । गांवों में रहने वाली अधिकांश जनता को अभी भी पीने का शुद्ध जल, स्कूल, सड़कें, औषध लय तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें उपा-लब्ध नहीं हैं। इसके बदले में वहां पर धूल, गोबर, बीमारी, निराशा अज्ञानता आदि का राज्य रहता है । इस प्रकार गांधी जी का स्वप्न अभी तक साकार नहीं हो पाया है ।

योजना बनाने वालों ने बड़ बड़ बांध, कारखाने तथा अन्य परियोजनायें तो बना डालीं किन्तु गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ साथ गावों में जल संभरण, सड़क निर्माण, स्कूल खोलने तथा औषधालय खोलने के लिए भी पृथक धन राशि निर्धारित की जानी चाहिए ।

सरकार के निर्माण कार्यों में धन का अपव्यय हो रहा है । इस दिशा में मितव्ययता की अत्यन्त आवश्यकता है ।

हमें विदेशी सहायता अपने देश की प्रभुसत्ता का सौदा कर के प्राप्त नहीं करनी चाहिये। ब्रिटेन ने काश्मीर के मामले में भारत के साथ जो दुहरी चाल चली है वह समाप्त की जानी चाहिये। चाहे हमें उससे सहायता मिले या न मिले । यदि हमने सहायता लेने में वही नीति अपनाई जो चीन ने अमरीका से मिलने वाली सहायता लेने में अपनाई थी, जिस के परिणामस्वरूप चीन साम्यवादी देश बन गया ; तो हमारी भी चीन जैसी ही दशा होगी ।

जनता का नैतिक उत्थान ही वास्तविक प्रगति है । गांवों में नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिये। भौतिकवाद और संपति मानवीय समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। उदाहरणार्थ अमेरिका संसार का सब से अधिक धनी उन्नत देश है । किन्तु वहां पर १२ प्रतिशत बच्चे मानसिक रोग से पीड़ित हैं। यह संख्या और अधिक बढ़ती जा रही है । इसलिए हमें आध्यात्मवाद में विश्वास रखना चाहिए । हमें निर्धनों की सहायता करनी चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह गांवों की स्थिति सुधारने तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे ।

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : मैं उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है किन्तु कृषि उत्पादन में कमी होने से देश के लिए समस्या पैदा हो सकती है। समूची अर्थ व्यवस्था पीछे पड़ती जा रही है। इस पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। लोगों का स्तर उठाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिएं तथा कृषकों को प्रोत्साहन और उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाया जाना चाहिए। तभी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कृषकों को कृषि के अतिरिक्त कुछ और रोजगार देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भूमि संबंधी सुधार किये जाने चाहिएं जिससे कृषक अधिक मेहनत से काम करके उत्पादन में वृद्धि कर सकें। जापान तथा अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रति एकड़ उपज बहुत कम होती है। इस कमी के कारणों को दूर किया जाना चाहिये।

हमारे देश में कृषकों के पास निर्वाह योग्य भूमि भी नहीं हैं वे ऋणग्रस्त हैं। सिचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। अनाज की मडियों का अभाव है। गांवों में रहने वाले कृषकों को यातायात की उचित व्यवस्था न होने के कारण आधुनिक प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यद्यपि सामुदायिक विकास द्वारा गांवों में बहुत किया जा रहा हैं किन्तु अभी बहुत किया जाना बाकी है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत अब तक केवल २ प्रतिशत से ४ प्रतिशत भूमि में ही वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जा रही है।

गांवों में विकास नगरों के विकास से पीछे रह गया है। गांवों के विकास के लिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई जानी चाहिए तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती की जानी चाहिए।

छोटी सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सिचाई का लक्ष्य १२८ लाख एकड़ निर्धारित किया गया है जो कि चालू योजना काल में पूरा किया जाना है किन्तु सीमेंट, लोहे और अन्य सामान की कमी के कारण इसके पूरा होने में संदेह है इसलिए सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि ६० लाख एकड़ भूमि में सिचाई की व्यवस्था है तथा ५०½ लाख एकड़ और भूमि में सिचाई की व्यवस्था के बारे में सरकार विचार कर रही है। यद्यपि लघु सिचाई, भूमि संरक्षण पशुपालन आदि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं में पर्याप्त धन निर्धारित किया गया है फिर भी इस दिशा में प्रशंसनीय प्रगति नहीं हो पाई है।

कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने पड़ते हैं। किन्तु उत्पादक को भी उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। मूल्य का अधिक भाग विपणन में चला जाता हैं। अतः एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया जाये जो देश के विभिन्न भागों में विपणन सम्बन्धी परिस्थितियों की जांच करे। उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाये और कृषि सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण करने के लिए कदम उठाये जायें।

उर्वरक के संतोषजनक वितरण की भी व्यवस्था की जाये। एक समिति स्थापित की जाये जो किसानों की कठिनाइयों का पता लगाये, कृषि की लागत के संबंध में जांच करें और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के संबध में सिफारिश करे। क्योंकि यह बात बेरोजगारी मिटाने और आर्थिक विकास करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

कल एक सदस्य हमारे देश के अल्पसंख्यकों के संबंध में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद भी मुस्लिम वर्ग इसी देश में रहना चाहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गृह कार्य मंत्री के आश्वासन ने उनमें कितना विश्वास पैदा कर दिया हैं। अच्छा है कि जोशीला भाषण देने के स्थान पर अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने के संबंध में कुछ रचनात्मक सुझाव दिये जायें।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : श्रीमान्, हमारी सरकार असफल सिद्ध हुई हैं। संविधान में यह दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। अतः यदि अल्पसंख्यकों में से एक को भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते तो सरकार असफल हो जाती है। हमारी सरकार कमजोर हैं। वह महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना चाहते हैं किन्तु वास्तव में वे उनके मार्ग से बहुत दूर हैं। गांधीजी कभी जिम्मेदारी से नहीं बचते थे। गांधी जी ने देश के विभाजन की खबर सुन कर कहा था कि यह साम्प्रदायिक संघर्ष अब राज्य स्तर पर चलता रहेगा। उनकी बात सच हुई है। भारत का कोई भी सच्चा

[श्री ह० प० चटर्जी]

सपूत विभाजन के पक्ष में नहीं था। कुछ दूसरे ही व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए विभाजन चाहते थे। श्री पटेल ने इस संबंध में कहा था कि एक तीसरा पक्ष इस बात को चाहता था कि हिन्दु मुसलमान परस्पर लड़ते रहें। इसलिए हमने यही उचित समझा कि विभाजन को स्वीकार करके विदेशी प्रभाव समाप्त कर दिया जाये।

अंग्रेज बंगाल का भी विभाजन करना चाहते थे। किन्तु राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले बंगालियों ने ऐसा नहीं होने दिया। १९४६ में पंजाब और बंगाल में उपद्रव होने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। मुस्लिम लोग ने "सीधी कार्रवाई" आरम्भ कर दी। इससे कांग्रेस के नेताओं को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के समय गांधीजी ने कहा था कि जो हिन्दू लोग भय के कारण पाकिस्तान में न रहना चाहें उनको यहां बुलाकर पूरी सुविधायें दी जानी चाहिये। गांधी जी हिन्दुओं की रक्षा चाहते थे। किन्तु उनके चेले क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में प्रव्रजन प्रमाणपत्र बंद कर दिये गये हैं। उन लोगों को चाहिये कि प्रभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें। पाकिस्तान की सीमा पर ट्रेन के पहुंचते ही जवान हिन्दू लड़कियों को, मान्य प्रव्रजन प्रमाणपत्र होने के बावजूद भी, गुंडे ले जाते हैं। उन्हें सीमा पर नहीं आने दिया जाता। हमारी सरकार चुप बैठी है। वह वहां सेना क्यों नहीं भेजती? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यदि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हों और पूर्वी बंगाल में न हों और यदि इस प्रश्न पर भारत पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दे तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। किन्तु उनके एक चेले ने, जो कि अब मंत्री नहीं है गोआ में सेना भेजने पर आपत्ति की थी जब कि महाराष्ट्र की मांग करने पर गांधी जी के उसी चेले के कारण बंबई की सड़कों पर लोगों का रक्त बहा था। वे गोआ में "शांति सेना" लेकर जाने को प्रस्तुत थे अब वे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए क्यों नहीं जाते? वे लोग विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वे अब भी भारत के नागरिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनने पर भी जिन्ना ने कहा था कि यहां अल्पसंख्यकों की पूरी तरह रक्षा की जायेगी। पाकिस्तान जिस आधार पर बना था वही समाप्त हो गया है।

यह डरपोक सरकार आदर करने योग्य नहीं है। पाकिस्तान के प्रति उन्होंने कायरतापूर्ण नीति अपनाई है। इसीलिए यहां भी वे साम्प्रदायिक भावनाओं को नहीं दबा पाते। पाकिस्तान की सरकार दंगे करवाती है। धीरे-धीरे पाकिस्तान से हिन्दू समाप्त किये जा रहे हैं। अमरीका और इंगलैंड इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहते। पवित्र बाल की चोरी का प्रभाव पाकिस्तान में इतनी दूर हुआ और वहां लूटपाट और हत्याकांड हुआ। ब्रिटेन और अमरीका अपने को सभ्य कहते हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान को शस्त्रों से सुसज्जित किया है। चीन भी पाकिस्तान की ओर है।

वे लोग काश्मीर पर हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं। हमें चाहिये कि हम पूर्वी पाकिस्तान पर उनके अधिकार को चुनौती दें।

हमारे भाई मुसीबत में हैं। उनकी भी वही संस्कृति और परंपरा है जो हमारी है। अमरीका के कारण पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई है। १९५४ में अमरीका में एक संधि की गई और पाकिस्तान को पूरी तरह शस्त्रों से सज्जित कर दिया गया।

पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल में पिछले दंगों के समय गांधी जी नोआखाली और बालियाघाट गये थे। अब मंत्रियों को चाहिये कि दंगों से ग्रस्त क्षेत्रों में जायें।

अन्त में मैं कहूंगा कि प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के संबंध में उन्हें सब प्रकार से सुविधायें दी जायें।

Shri Mahesh Dutta Misra (Kandwa) : Mr. Deputy Speaker, while expressing my thanks for the Address delivered by the Vice-President discharging the functions of the President. I would like to submit that this is not the proper time for going into the details and fixing responsibility on Govt. or on some other party. Reference has been made to our achievements as well as our weaknesses in the Address. The major issue which has most affected us, that of looting and killing in East Pakistan, has been dealt separately.

We have to consider this issue from all the possible angles, as it is not a mere problem of minority, here or in Pakistan. Rather it is a wider issue having international complications and as such, should be viewed considering all its diplomatic consequences. These riots are different in character, from the riots that took place during pre-partition days, instigated by British rules to strengthen the demand for Pakistan. Then, we could freely comment on those disturbances. But now the position is quite different. The secular character of our country has devolved some responsibilities on us.

We were forced to accept two-nations theory by the circumstances. But now, when Pakistan has been formed it is our moral duty to protect the minorities which have cast their lot with India.

It has been said that few disturbances, which unfortunately took place in Calcutta and other areas, were instigated by Pakistan's agents. I admit that Pakistan's agents or any other Indian national having vested interest in Pakistan might have tried to foment these troubles and riots. But if these riots assume greater magnitude, it becomes the responsibility of the Govt. and of the people of India. We view this problem in this perspective. This was the reason why Shri Nanda adopted sternest measures to control this situation, for which he has been eulogised almost all over the country. Nevertheless there had been few communal elements who did not approve if stringent measures adopted by him. Such elements, directly or indirectly, strengthens Pakistan's hands.

We appreciate the feelings of our Bengali brethren. It is but natural for them to become excited. But if we take pains to see that not a single person belonging to minority is harassed in our country in any way, we will have that moral support to refer the case to the U.N.O. and if the case is not settled there, then, we can ever go to the extent of invasion; for settling this issue. But our case weakens if suffering is inflicted on minorities in our country. I would like to stress that there are still some elements in the country who provoke communal feelings. If we do not save the people from the vicious effect of the propaganda, being carried by some newspapers and otherwise, it is natural that the troops and the police will not be able to do much for secularism.

It is not merely an Indo-Pak Problem. There are some countries who do not like our policy of non-alignment which we have adopted in order to achieve peace and co-existence in the world at large.

These countries are from the very beginning have intrigued to foil our efforts. The same imperialistic powers, forced to renounce their rule over

[Shri Mahesh Dutta Misra]

their dominions, excite the feelings of casteism, racialism and communalism before they leave. They do not want to see democracy, socialism or secularism flourishing in Asia or Africa.

Some people in our country want us to join this or that block. The first thing is that in the situation which prevailed from 1947 to 1963, it was not possible for us to align with any block. We made it clear in plain words. Seen from one point of view, our policy has been successful. In Security Council our case was only weakened by the riots which took place in calcutta. Though they were insignificant compared, with what happened in Pakistan.

I would like to give some concrete suggestions for maintaining communal peace in our country.

First of all you should try to follow some programmes for inspiring mutual goodwill among different castes and try to remove feelings of enmity and mistrust from their hearts.

In the conclusion, I would like to say that we should try to view this whole situation in our international perspective. We are not secluded from rest of the world. Muslims, Christians and Buddhists all have to live together in this country. To talk of the interest of any single community exclusively is meaningless. We have to remove the feelings of distrust and then along we will be able to sustain age old prestige, which some anti-social and anarchic elements are try to injure. But they will not succeed in their evil efforts. I have full hope in my country man.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर): खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उपराष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीनी आक्रमण के समय खोये हुए राज्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने, आपातकाल के जारी रखने, अहिन्दी भाषी लोगों में विश्वास उत्पन्न करने, लंका और बर्मा के भारतीयों के अधिकारों, मद्रास का नाम बदल कर तामिलनाद रखने, मूल्य वृद्धि, जीवनस्तर के गिर जाने, बेरोजगारी की समस्या, बढ़े हुए करों, अल्पसंख्यकों की स्थिति आदि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं डाला।

गत वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकालीन भावना का आभास था और कर्तव्य की पुकार सन्निहित थी। राष्ट्रपति ने तब कहा था कि देश की स्वतन्त्रता और सम्मान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। अब सत्तारूढ़ दल ने आपातकाल की आवश्यकता को विस्मृत कर दिया है। गत वर्ष के अभिभाषण में ३० परेग्राफ में से परेग्राफ ६ से १५ चीनी आक्रमण के संबंध में थे। इस वर्ष केवल २ या ३ परेग्राफ हैं। परेग्राफ १४ में कहा गया है कि चीनी संकट अब भी हमारे सामने है। "आक्रमण" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि चीन सीमा पर अपनी सेना का जमाव बढ़ा रहा है।

आपातकाल की घोषणा करने के बाद कांग्रेस कार्यकारणी समिति ने यह संकल्प पारित किया था कि हम अपने मतभेद भूला देंगे और आक्रमणकारी को खदेड़े बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उस समय संसद और प्रधान मंत्री के आह्वान पर सब संगठित हो गये थे। राजनैतिक मतभेद भुला दिये गये थे। आपातकाल का मूल उद्देश्य आक्रमणकारी को खदेड़ना और देश की शक्ति को बढ़ाना था किन्तु गत एक वर्ष से सत्तारूढ़ दल देश की शक्ति बढ़ाने के स्थान पर स्वयं की शक्ति बढ़ा रहा है। इसी ध्येय के लिए उन्होंने कामराज योजना बनाई है। उन्होंने यह समझा है कि इस योजना से देश की समस्त बुराइयां दूर हो जायेंगी और उसका

काया कल्प हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह उनका भ्रम है। एक विख्यात कांग्रेसी ने कामराज योजना के संबंध में कहा है कि यह योजना इस भ्रम पर आधारित है कि कांग्रेस का उचित रूप से कार्य करना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, किन्तु प्रजातन्त्र में सत्तारूढ़ दल का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसकी सरकार कैसी है, उसके अन्दरूनी कार्य से नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि एक अन्य बात है जिससे कांग्रेसी नेताओं का भी विश्वास डगमगा उठा है यह है कि कुछ राज्य सरकारें असफल सिद्ध हुई हैं। कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। यह बात एक विख्यात कांग्रेसी ने कही है। अतः कामराज योजना दल को शक्तिशाली बनाने के लिए है देश को नहीं। इस समय आपातकाल में जब कि देश की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिये कांग्रेस दल अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। इस सीमा तक वह असफल सिद्ध हुआ है कि उसने आपातकाल की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसलिये पूरी स्थिति पर फिर से विचार करके आपातकाल समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उप चुनाव जो आपातकाल के कारण स्थगित कर दिये गये थे अब कर लिये गये हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आपात कालीन स्थिति में सुधार को देखते हुये चुनावों को, स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये आपातकाल को समाप्त कर दिया जाये।

वे यह तर्क भी उपस्थित कर सकते हैं कि अभी हमें सैनिक शक्ति बढ़ानी है। किन्तु यह एक दीर्घकालीन आवश्यकता है। जब तक पृथक-पृथक देशों का अस्तित्व रहेगा, जब तक सारी दुनियां मिल कर एक नहीं हो जाती तब तक हमें सैनिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता बनी ही रहेगी। इसके लिए आपातकाल की आवश्यकता नहीं है।

इस वर्ष द्र० मु० क० दल के सदस्य उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उपस्थित नहीं थे। इसका अर्थ उनका अनादर करना नहीं है। हिन्दी समर्थकों की बढ़ती हुई, असहिष्णुता के विरोध में ऐसा किया गया था। १९६२ में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने पहले हिन्दी में अपना अभिभाषण पढ़ा था। हम चुपचाप सुनते रहे, यद्यपि उसका एक भी शब्द हम नहीं समझ पाये थे। किन्तु १९६३ में जब डा० राधा कृष्णन बोल रहे थे तब हिन्दी के समर्थकों ने विरोध किया। इसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके समक्ष अधिकतर साक्ष्य हिन्दी में दिये गये थे।

इस वर्ष भी बजट सत्र आरम्भ होने के पहले ही इस संबंध में विवाद आरम्भ किया गया था और यह अपील की गई थी कि राष्ट्रपति हिन्दी में नहीं तो तेलगू अथवा तामिल में अपना अभिभाषण दें। किन्तु संविधान में अंग्रेजी और हिन्दी, दो ही भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसलिए ऐसी अपील करने के पहले संविधान का संशोधन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये थे।

इस वर्ष भी बजट सत्र आरम्भ होने से पूर्व ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में यह भाषा विवाद आरम्भ हो गया था। मांग की गयी कि राष्ट्रपति या तो हिन्दी में बोलें अन्यथा अपनी मातृ-भाषा तेलगू में बोलें। परन्तु यह मांग करने वाले डाक्टर साहब वैसे तो बहुत ही विद्वान हैं, परन्तु यह भूल गये कि संविधान के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी इन्हीं दो भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति तामिल, तेलगू अथवा अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा में भाषण करे तो हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा। मेरे विचार में राष्ट्रपति को किसी विशेष भाषा में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की उनको छट रहनी चाहिए।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हिन्दी प्रेमियों में असहिष्णुता की भावना का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, चिन्ता की बात है। इस सन्दर्भ में मेरा यह भी कहना है कि हिन्दी प्रेमियों ने संसद में

[श्री सेझियान]

राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण के लिए भाषा के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय हाल में जो विवाद उठाया था, वह बहुत ही खेदजनक बात है। इससे हिन्दी वालों की कट्टरता ही झलकती है जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता।

लोगों में जो यह धारणा फैला दी गयी है वह भी गलत है कि 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम' हिन्दी की प्रगति के विरुद्ध है। हम हिन्दी के बिलकुल विरुद्ध नहीं हैं। यदि अंग्रेजी की तरह हिन्दी काम कर सके तो हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बारे में खेद की बात यह है कि जो लोग हिन्दी के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, वे इसमें सुधार करने की दिशा में कुछ नहीं कर रहे। उनका दृष्टिकोण तो केवल यह रहता है कि जो लोग हिन्दी नहीं चाहते उन पर हिन्दी लाद दी जाय। मेरा मत यह है कि इस दिशा में जब तक अपेक्षित सुधार और समुचित सहिष्णुता न दिखाई जाय, हिन्दी लागू कर देने की तिथि नहीं निर्धारित करनी चाहिए। मेरा सुझाव तो यह है कि इस समस्या पर विचार करने के लिए प्रमुख विद्वानों, राजनीतिज्ञों और अन्य सम्बद्ध लोगों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय। इस सम्मेलन में इस समस्या का हल तलाश किया जाय। मैं इस बात की अपील करना चाहता हूं कि मामले को ठण्डे दिल से मेरे बताये सुझावों के अनुसार हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

Shri S. N. Chaturvedi (Ferozabad): We are amidst the Communal fire. Before I take up the matter, I would like to say a few words regarding the language problem. I think it was not correct and fair to say that there was any attempt to impose Hindi on the non-Hindi Speaking people. It was only to respect the wishes of the non-Hindi Speaking people that the Bill was recently passed for the continuance of English for an indefinite period. But then we have to think seriously in order to have a national language The language which has to be our national language cannot be a foreign language. This matter had already been decided after mature consideration that Hindi, which is understood and spoken by a vast majority in this country, would be our national language. The question of imposition does not arise at all.

Now, I come to the problem which is engaging our attention at the present moment. It is really unfortunate that there were communal riots in this country. I admit that every possible Protection should be given to the minorities in India. We should strongly condemn every communal incident But it is not proper to put at par the incidents in India with what happened in East Pakistan. We should not forget that in East Pakistan there was an organized and planned massacre of the minorities. And all this was undertaken with the connivance of the Government and the leadership. The Pakistan Government had all along tried to crush people's movements for a democratic set up in Pakistan, and in order to divert the attention of the people from that side, they created some troubles like this occasionally. Therefore, we must understand the game of Pakistan. The Government of India was quick enough to control the situation here, but in East Pakistan the people of the minority community were still in great difficulties.

In our country, a disturbing feature has been that a wrong propaganda is being carried out by some elements, that Muslims in India had no rights at all. They are regarded as second class citizens. This element is still inciting the people. My submission is that it was against this element that we had to guard ourselves. Such people are responsible for the troubles. The Government should be vigilant about pro-Pakistan and pro-China forces actively working in this country.

It is really shocking, that there have been failures on the agricultural fronts. It is requested that Government should take more concrete steps to increase production. I think, we should adopt on new methods, but the cultivators should also be helped by improving their present methods. We should also pay more attention towards our villages. Proper type of educational facilities should also be provided to the rural population, so that they may be able to get some employment at the later stage. This is very important matter, and Government should give it careful consideration.

डा० उ० मिश्र : मुझे यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि यदि यह सच है कि कलकत्ता में दंगे मुसलमानों द्वारा नगर में पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त की सहायता से किये गये हैं, जैसा कि परसों कांग्रेस दल के एक सदस्य ने अपने भाषण में कहा था, तो उस समय सरकार कहां थी। सरकार को इस बारे में पूर्व सूचना क्यों न प्राप्त हो सकी। सरकार को आपातकलीन शक्तियां आप्त हैं, यदि इन शक्तियों का प्रयोग श्रमिक संघों पर हो सकता है तो क्या कारण है कि उसका प्रयोग उन उपद्रवियों के विरुद्ध न किया जा सका। मेरा निवेदन है कि इन दंगों के कारणों की बड़ी गहराई से जांच की जाय। और इसका इलाज करने का कोई ढंग निकाला जाना चाहिये। गलत बात कहकर अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए। हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं। हमें कभी भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का तो आधार ही घृणा है।

हमारे नेता यह समझते हैं कि साम्राज्यवाद के दिन चले गये। परन्तु ऐसी बात नहीं है। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो रवैया अपनाया वह इस बात का ताजा प्रमाण है। हम यह समझने लग गये हैं कि हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है अतः कोई हमारे विरुद्ध नहीं बोल सकता। हमें वह बात हमेशा अपने समक्ष रखनी चाहिए कि साम्राज्यवादी शक्तियां हमेशा अपना गंदा खेल खेलती आई हैं।

[Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

यह बात भी तो सर्वविदित है कि पाकिस्तान की स्थापना भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चालों के ही परिणामस्वरूप हुई थी। और यह भी तथ्य की बात है कि वह अमरीकी सहायता पर अब तक जीवित रहा है। सरकार को यह बात निश्चित कर देनी चाहिए कि देश में विदेशी पूंजी का जो प्रयोग होगा वह देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दृष्टि में रख कर होगा। जो भी विदेशी काम इस देश में हो उस में भारतीय कर्मचारी लगाये जाने चाहिएं। और ऐसे उपक्रमों को भारत की अर्थव्यवस्था पर छाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्कल मशीनीरी में जो ४० से ५० करोड़ का विनियोजन किया गया है, उस में इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया। इस में से आधे से अधिक पूंजी तो वेतनों में ही चली गयी। इस परियोजना में एक भी भारतीय इंजीनियर नहीं था।

हम समाजवाद का निर्माण किस आधार पर करेंगे यदि हम ने अपनी आय श्रमिकों में न बांटी। सरकार ने लोगों को २ रुपये बढ़ाये हैं, हालांकि उसे पता है कि चीजों की कीमतों में भयंकर रूप से वृद्धि हुई है। श्रम जीविकों को राष्ट्रीय आय में से उनका उचित अंश मिलना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता देने के उत्तरदायित्व से बचने के लिए सरकार को रहन सहन की लागत के देशनांक गड़ने की आदत को छोड़ देना चाहिए।

[डा० उ० मिश्र]

देश में भ्रष्टाचार का आरम्भ इस तरह हुआ है कि जिन लोगों के हाथ में एकाधिकार है वे लोग खास खास राजनीतिक दलों का ही साथ देते हैं। इस बुराई को मिटाने का एक ही तरीका है कि देश में एकाधिकारों की शक्तियां कम कर दी जाएं। देश की आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से बचाना चाहिए। इस के अतिरिक्त भाषाई दमन भी हुआ है। लोकतंत्र की ऊंची बातों के बावजूद कुछ राज्यों में यह दमन जारी है। आदिवासी क्षेत्रों में यह बहुत अधिक है। आदिमजाति विद्यार्थियों को उनकी मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। ६०, ७० स्कूल हैं परन्तु उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था केवल २ स्कूलों में है। हमें इस रोग का उपचार करना चाहिए इस से भागना नहीं चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर): उपराष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में लगभग सारी बातें कह दी हैं परन्तु मैं इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय द्वारा गणतंत्र दिवस पर दिये गये सन्देश की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। उसको विचार में लाते ही हम वास्तविकता के कुछ निकट आ जाते हैं। इस संदेश में राष्ट्रपति ने बहुत व्यंग-पूर्ण ढंग से इस बात का संकेत दिया है कि निर्बल, अदक्ष तथा दूषित प्रशासन को बहुत अधिक दिनों तक सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि यदि भ्रष्टाचार, पक्षपात, और चोरबाजारी को प्रभावशाली ढंग से न सुलझाया गया तो हो सकता है कि लोग तंग आकर अपने रास्ते चलने लग जाएं। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कुछ राष्ट्रपति ने कहा है सरकार उसकी उपेक्षा नहीं करेगी। भारत के मुख्यन्यायाधिपति ने भी अपने भाषण में कहा है कि आज देश का सामान्य व्यक्ति प्रशासन की शुद्धता को सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है। श्री नन्दा जी का सतर्कता आयोग इसका इलाज नहीं है।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार को राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की यह सिफारिश अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये कि भ्रष्टाचार के मामलों का निर्णय करने के लिए मुख्य न्यायाधिपति के पद का एक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सब से महत्व-पूर्ण बात यह है कि लोगों की शिकायतें दूर की जाएं। सरकार को केवल निजी हितों को को ध्यान में रख कर ही निर्णय नहीं करने चाहिं। इस समय मंत्रालयों के संगठन का काम बहुत ढीला है, इसे दूर किया जाना चाहिये। मेरे विचार में विभिन्न मंत्रालयों के बीच ठीक प्रकार से प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपप्रधान मंत्री होना चाहिये। बिना विभाग के ऐसे मंत्रियों से काम नहीं चलेगा। जिनके पास विशेष प्रकार के काम हो।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तान एक समस्या प्रधान देश है। उसकी उपज ही साम्प्रदायिकता तथा घृणा से हुई है। और ये साम्प्रदायिकता तथा घृणा के सूत्र अब भी वहां बने हुए हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश कूटनीति भी इसके लिए जिम्मेदार है। हाल ही में काश्मीर के प्रश्न सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन ने जो रवैया अपनाया उस पर हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रिटेन की सहायता, उसे इसके बावजूद भी मिल रही है कि वह चीन के साथ दोस्ती कर रहा है। हमें ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि यदि इसी तरह से होता रहा तो हमें उस देश के

सम्बन्धों के बारे में पुनः सोचना होगा। अमेरीका को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि पूर्व में लोकतन्त्र के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि भारत की पूर्ण रूप से सहायता की जाय। हमें पाकिस्तान की मनोवृत्ति को समझना चाहिए और भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में नहीं रखना चाहिए।

यह आश्चर्यजनक है कि ब्रिटेन वास्तविकता को नहीं देखता है। पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है। पाकिस्तान के काश्मीर के क्षेत्र से न जाने के कारण ही जनमत संग्रह की मांग स्वीकार नहीं की जा सकी है। पाकिस्तान की शरारत के कारण ही आसाम में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग आये हैं। पूर्वी पाकिस्तान में हुए हत्याकाण्ड के लिये भी वही जिम्मेदार है और इन सबके बावजूद भी पाकिस्तान ही संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत ले जाता है। अतः अब समय आ गया है कि हम इस मामले में एक दृढ़ दृष्टिकोण अपनायें तथा अपने मित्र देशों को यह जता दें कि हम इस बारे में गम्भीर हो गये हैं।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हमें कोलम्बो प्रस्तावों की बात को अब छोड़ देना चाहिये। चीन एशिया तथा अफ्रीका में अपना भारत-विरोधी प्रचार जोरों से कर रहा है। पाकिस्तान को भी उसने अपने साथ मिला लिया है ताकि जहां तक पश्चिमी राष्ट्रों का सम्बन्ध है, वह भारत से टक्कर ले सके। चीन अपनी स्थिति दृढ़ कर रहा है जो कि भारत के हित में नहीं है। अतः सरकार को देशवासियों को यह बता देना चाहिये कि वह चीन से भारतीय राज्य क्षेत्र को खाली करवाने के लिये कोई कार्यवाही करने में कभी संकोच नहीं करेगी। हमें चीन के भारत-विरोधी प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिये एफ्रो-एशियन देशों में अपने प्रचार को अधिक तीव्र करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने का कारण यह है कि कृषकों को कृषि आवश्यकताओं का ठीक समय पर सम्भरण नहीं किया जाता है। हर स्तर पर सहयोजन की अत्यधिक कमी है। जब तक प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित नहीं किया जाता कृषि उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव है।

आपातकाल में भी हमारे औद्योगिक उत्पादन में केवल ७ से ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब तक यह वृद्धि ११ से १२ प्रतिशत तक नहीं होती हम इस अवरुद्ध स्थिति से नहीं निकल सकते। यदि हमें समाजवाद को बढ़ावा देना है तो हमें लघु उद्योगों को महत्व देना चाहिये। प्रधान मन्त्री तक ने भी कहा है कि छोटे उद्योगों को हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। परन्तु दुख की बात यह है कि इस उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करन के लिये केवल एक मात्र संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है और इस निगम ने भी नवम्बर, १९६२ से अब तक एक भी आवेदन स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। बड़े उद्योगों के लिये २० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो सकती है परन्तु लघु उद्योगों के लिये एक पाई भी विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है। तीसरी योजना की अवधि में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा १२ करोड़ रु० की राशि पृथक रक्षित की गई थी। परन्तु उसमें से आधा करोड़ राशि भी अब तक व्यय नहीं की गई है। हमारे आर्थिक आयोजन की यह दशा है।

हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री दोनों अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। उन दोनों में आपस में विवाद की कोई सम्भावना नहीं है। हमारे प्रधान मन्त्री एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। परन्तु कुछ ऐसे लेख लिखे गये हैं कि प्रधान मन्त्री से शक्ति राष्ट्रपति भवन में आ गई है। हमें इन चेतावनियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। और स्थिति को सदैव के लिये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये ताकि बाद में कोई कठिनाई पैदा न होने पाए।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी तटस्थता की नीति एक सराहनीय नीति है । परन्तु समय के अनुसार इसमें फेरबदल करने की आवश्यकता है । हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति तभी सफल सिद्ध हो सकती है जब हम देश की आन्तरिक शक्ति बढ़ायें । इसके लिये हमें आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देना चाहिये और प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिये ।

Shri Rameshwaranand (Karnal): The floods cause great have in the country every year. I come from a flood affected area where out of 10 villages lying near the Jumna 5 have already been washed away by flood waters. The Address does not make any mention of the steps that Government have taken or propose to take to save the country from floods.

So far as education is concerned the arrangements made for imparting it are not satisfactory. The main cause of all our failures is that education here is imparted in English. The people receive education not for helping the cause of the country but with a view to get employment. This is why no work is done in the offices. The big authorities do nothing and thrust their work on their juniors. They are paid high salaries. Streamlining of the whole administration is necessary to make the implementation of the plan a success.

Mention has been made about socialism in the vice-President's Address. The President, Prime Minister and other Ministers live in palatial buildings with big lawns adjoining them. These lawns are well maintained by providing water and manure. On the other hand, in several areas of the country the crops suffer for want of irrigation and manure. I, threrfore, fail to understand what kind of socialism the Government is aiming at. It would have added to the prestige of the country if the President and Ministers would have occupied the flats in which the Members of Parliament live.

In the matter of foreign exchange, we depend on our foreign friends. I want to ask how long the country can prosper on the basis of foreign loans.

I was under the impression that the Indian Parliament represents the people of India, but from the speeches that have been made here it appears that some of them are agents of China and Russia and some represent Pakistan. There is no comparison between India and Pakistan. In the recent communal disturbances in East Pakistan thousands of Hindus were killed but here in Calcutta again the Indian police shot dead many Hindus. I do not want that we should harass persons of a different faith. But how long can the Government suppress these things. If Hindus are eliminated from India, the civilisation and culture of the Hindus will also vanish with them. On the other hand if Christians and Muslims quit India, there are many countries to propagate and spread those religions. I believed that after partition Hindus and Muslims would live as brethren. But it has now been proved beyond doubt that so long Pakistan exists in the east and the west of India, these communal disturbances in and outside India cannot be eliminated. There are numberless people in India who have the cause of Pakistan at their heart. But we can imagine the number of well-wishers of India in Pakistan. Many high posts in India are held by persons of other communities. On the other hand this is not the position in Pakistan. The Hindus in Pakistan want to come over to India, but Muslims in India do not want to leave this country. We should therefore take lessons from all these things.

It is said that we are wedded to peace. But in old age everybody pratices peace. In the whole Cabinet you will not find even a single youngman. Government is not run like that.

The prices are rising. The only remedy is that any one drawing more than Rs. 500/- should not be given Rs. 500/- as salary and the rest should be distributed among persons drawing less than Rs. 100/-. Salaries and allowance should not be increased, because it will lead to more taxes and more taxes mean rise in prices.

It has been said that agricultural production has gone down by 3 per cent. But actually it has gone down by 8 per cent during the last 2-3 years. A sum of Rs. 19 crores and 15 lakhs has been earmarked for effecting increase in agricultural production. But in practice not a single naya paisa reaches the agriculturist Therefore, to effect increase in production the farmer should be given more mony and try to solve his difficulties. Controls and other restrictions imposed on certain commodities like gur come in the way of the villagers. The wheat supplied through fair price shops is not wholesome. Government should honestly look into this matter.

An hon. friend here made some criticism against Hindi, which pained me very much. An opinion poll may be conducted. If Hindi gets a majority, it should not be criticised. I am ready to abide by the verdict of the people, in this regard. I have addressed people in Telengana, Hyderabad etc. in hindi. People do not understand English. They like to be addressed in Hindi. We should see the realities and leave aside politics. I am pained to see that even after sixteen years Government have not been able to introduce Hindi in the administration. Honest efforts have not been made to give Hindi its rightful place.

There is restlessness in the country everywhere. There has been an unprecedented increase in the number of divorce cases, family fends, quarrels between Harijans and non-Harijans, slaughter of cows and what not. The Congress Government is responsible for all these things. If the congress boasts of being follower of Gandhiji, they should put his policies into practice, without any hesitation.

Shri Gopal Datt Mengi (Nominated—Jammu and Kashmir): I rise to express my gratitude to the Vice-President for the Address he was pleased to deliver to both Houses of Parliament. There has been alround progress in all fields. But in some directions we have not been able to make much headway. In the agricultural field, land reforms have not been into seduced. The agriculturists have not been assured fair prices for their produce. Government have failed to provide them better seeds, better implements and cheap irrigation facilities. Expert advice is also not made available to the farmers. All these things have led to shortfall in production. We should make use of community development and Punchayati Raj institutions to see to the difficulties of the farmers and render them the necessary assistance.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

China has occupied a large portion of India and in conspiracy with Pakistan has taken away a sizeable portion of Kashmir. China has also rejected the Colombo Proposals. We should, therefore, set up border guards and local militia in border districts to ensure the security of that area. We should also make our stand, geographical and ideological, clear to our own security personnel.

[Shri Gopal Datt Mengi]

To counter act border raids from the Pakistani side we should settle ex-service men in the border areas. This will also help in checking infiltration and smuggling.

Now, I want to say something about the theft of the sacred relic from the durgah of Hazratbal. The people of Kashmir were in grief by its theft. Some demonstrations took place there but they were peaceful. Communal feelings were not roused. Some bungling took place after the recovery of the sacred relic. An I. A. S. Officer of the Government of India declared that whoever refused to identify the relic would be termed as Pakistani. But Shri Lal Bahadur Shastri went there and restored confidence among the people there. Though the relic has been restored yet the action committee is still functioning there. One member of the action Committee is Maulana Masoudi. There is no doubt that Maulana Masoudi and Sheikh Abdullah played great part in the accession of Kashmir with India. Maulana Masoudi now says that Gulam Abbas and Maulana Mir Vaz should be recalled from Pakistan and then we may sit together and finalise the future set up of Kashmir. He forgets everything that has happened in Kashmir after 1947. The constituent Assembly of which Sheikh Abdullah was a leader, has accepted the final accession of Kashmir with India. Unless Maulana Masoudi accepts the *status-quo* in Kashmir, how can he be taken in the Kashmir Cabinet when his very faithfulness towards India is questionable. He also pleads for the release of Sheikh Abdullah. But before doing so, we should make sure about his stand on Kashmir. Whether Sheikh Abdullah accepts the present jurisdiction of the Constituent of India over Kashmir. Unless he agrees to the *status-quo*. it is not advisable to interfere in the legal proceedings that are going on against Sheikh Abdullah. Government will be inviting trouble if they do not heed these things.

It is said that there is corruption prevalent in Kashmir. But corruption is there in India also. The fact is that it has developed into a national disease and it has to be solved on the national level. It has also been said that the Government in Kashmir is inefficient. There is a whole history behind it. In 1953, when Sheikh Abdullah deflected several leaders of the nationalist movements and some heads of department also left the arena with him. It gave a great setback to the Administration. Bakhshi Ghulam Mohammed mustered the depleted nationalist forces tried to carry on the administration. In 1957, the National Conference suffered a similar set-back, with the deflection of G. M. Sadiq. He re-entered the Kashmir Cabinet in 1960. The departments that were held by Mr. Sadiq and his followers in the Cabinet are Industries Transport, Public Works Department and Education. There are the departments about which there has been a talk of corruption. But I am at a lose to understand why this campaign of villification has been launched against Bakhshi Saheb. After all, he has served the country.

I admit that the administration there is weak and as such should be toned up. I hope the Home Minister will do the needful in the matter. The situation there should be viewed in proper perspective and no heed need be paid to this campaign of villification being carried on against Baskshi Saheb.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : I wholeheartedly support the motion of thanks on the Vice- President's Address. The Vice-President has drawn our attention to the social structure that we want to establish in this country. But with the speed with which we are progressing it will take us many years to accomplish the object in view. We cannot solve the food problem by shifting the policy in regard to food

production every year. Our population is increasing at the rate of one crore every year. Keeping this in view we should plan for a period of at least 10 or 15 years. I venture to suggest that in cities with a Populatioh of five lakhs, statutory rationing should be introduced and ration supplied to the population at fixed rates. In my opinion the fair price shops are not a right solution to this problem.

People in the villages are not getting sugar. They are experiencing great difficulties on account of falty distribution system. The Central Government should not leave it to the State Governments ini ts entirety. When it introduces control, it should ensure that proper arrangements are also made for distribution. If a State Government is in need of some commodity she should purchase it direct from the surplus State Government and the businessmen should not be brought in and allowed to indulge in profiteering. Farmers should be assured fair prices for their produce. They should be supplied with good seeds, credit facilities, fertilisers and irrigation facilities.

The Agricultural Board should be given wide powers and entrusted with the responsibility of taking any steps to effect increase in agricultural production. The rising prices have created restlessness among the people. Government can only afford to ignore this problem anymore at the risk of its becoming more and more unpopular.

भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re: MISSING OF I.A,F. AIRCRAFT

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे सभा को यह सूचना देते हुए खेद है कि भारतीय वायुसेना का एक विमान जो १७-२-६४ की शाम को श्रीनगर से ऊधमपुर को उड़ान कर रहा था १६.११ बजे से लापता है। उसमें मेजर जनरल आर० एस० ग्रेवाल तथा ब्रिगेडियर जे० एम० दास अन्य वायुसेना कर्मचारियों सहित यात्रा कर रहे थे। ये सरकारी कार्य से ऊधमपुर जा रहे थे। उन्होंने श्रीनगर से १५.०० बजे इल्युशीन १४ विमान द्वारा उड़ान की। इस विमान की तलाश जारी है। विमान के चालकगण तथा यात्रियों के निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है। नवम्बर के बाद एक के बाद एक दुर्घटना होती चली जा रही है। केवल विभागीय जांच से ही काम नहीं चलेगा। इसकी जांच एक संसदीय आयोग द्वारा की जानी चाहिये। आयोग की सहायता के लिये कुछ विशेषज्ञ भी उसमें रखे जा सकते हैं। इस मामले में सामान्य जांच से काम नहीं चलेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या यह दुर्घटना गत वर्ष हुई दुर्घटना के स्थान पर के निकट हुई है ? सीमा से वह कितनी दूर है ? सन्देह किन पर है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरी राय में यह दुर्घटना उस क्षेत्र में नहीं हुई है। वह एक डकोटा था जो बनिहाल दर्रे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं पुंछ के निकट हुई दुर्घटना के बारे में पूछ रही हूं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं। यह एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र है।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह तोड़फोड़ का मामला है ? इसकी विशेष जांच की जानी चाहिये। मिग् विमान काश्मीर क्षेत्र में भी दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वह दुर्घटना चण्डीगढ़ में हुई थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि सदस्यगण मृत व्यक्तियों के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े हों ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विमान अभी लापता है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम आशा करते हैं कि कुछ व्यक्ति बच गये हों । मन्त्री महोदय को इस बारे में जो सूचना प्राप्त हो वे उसे तुरन्त सभा को दे दें ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १९ फरवरी, १९६४/३० माघ, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday February, 19th 1964. Magha 30, 1885 (Saka)

GMG IPND—LS III—2228 (ai) LSD—18-5-64—600.